

घटना घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 140 - सोमवार 23- मार्च 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सक्षिप्त समाचार

सत्ता में आने के लिए बहुजन समाज का एकजुट होना जरूरी : मायावती

स्टेट कार्यालय, 22 मार्च 2026

लखनऊ, 22 मार्च 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि बहुजन समाज की सुरक्षा व अस्मिता के मिशनरी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुजनों को एकजुटता जरूरी है। एकजुट रहकर मुस्लिमों के साथ कार्य करते हुए चुनावी सफलता अर्जित करना समय की सबसे बड़ी मांग है। वरना आरक्षण सहित बहुजनों के हित व कल्याण के अहम मामलों में विरोधी पार्टियों की सरकारों की कथनी व करनी में अंतर है। इनके वादे और दावों व जमीनी हकीकत में भारी अन्तर्विरोध एवं नीयत व नीति में खोट के कारण हालात बद से बदतर होते चले जायेंगे। बसपा प्रमुख रविशंकर को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक की। इसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीते दिनों दिए गए कार्यों की समीक्षा में बेहतर परिणाम मिलने पर बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं की कार्यों की सरहना की। बैठक को सम्बोधित करते हुए मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश, बिहार प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ती हुई जातिवादी आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव से पहले सरकारों की ओर से दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से से खुद को बचाना होगा ताकि आने वाले पांच साल उनके लिए 'अच्छे दिन' के बजाय और ज्यादा बुरे दिन न साम्बित हों, जैसा कि इन दोनों राज्यों का भी पिछला अनुभव रहा है।

तमिलनाडु वाइवुरिमे काची ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम गठबंधन से तोड़ा जाता

चेन्नई, 22 मार्च 2026। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की सरगमों के बीच तमिलनाडु वाइवुरिमे काची (टीवीके) ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले धर्मान्ध्र प्रगतिशील गठबंधन (एएसपी) से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा पार्टी प्रमुख वेलमुगन ने रविवार को चेन्नई में प्रेस वार्ता के दौरान की। वेलमुगन ने बताया कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक द्रमुक गठबंधन का हिस्सा रही है और कई चुनावों में साथ मिलकर काम किया। इस बार भी द्रमुक के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई, लेकिन पार्टी को केवल एक सीट देने का प्रस्ताव दिया गया, जबकि उन्होंने दो सीटों की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले चरण की बातचीत में ही अधिक सीटों की मांग रखी थी और हाल ही में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि अतिरिक्त सीटें नहीं मिलीं तो गठबंधन छोड़ दिया जाएगा। इसके बावजूद द्रमुक की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सैन्य प्रदर्शन में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने दिखाया कौशल



जोधपुर, 22 मार्च 2026। इंडियन आर्मी की खड़गा कोर ने एक्सरसाइज जल विजय के तहत राजस्थान के रेगिस्थान में इंदिरा गांधी नहर के जल क्षेत्र में अपनी युद्ध क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस दौरान फाइटींग फॉर्मेशन ने पानी जैसी चुनौतीपूर्ण बाधा को पार करते हुए तेज गति और सटीक रणनीति का बेहतरीन परिचय दिया। जानकारी के अनुसार अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जल अवरोधों को पार करने की रणनीतियों को परखना और युद्ध जैसी परिस्थितियों में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता को सुनिश्चित करना था। सैनिकों ने आधुनिक उपकरणों और सुनियोजित रणनीति के साथ नहर को पार किया, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता और तालमेल साफ नजर आया। इस दौरान खड़गा कोर ने अपनी उभयचर क्षमता का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह क्षमता सेना को रेगिस्तानी और जलप्लवक दोनों तरह के इलाकों में प्रभावी ढंग से ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है।

पीएम मोदी की पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल बैठक... शाह-नड्डा, पुरी समेत सीनियर लीडर मौजूद रहे... गैस-तेल और ऊर्जा की स्थिति पर चर्चा की

नई दिल्ली, 22 मार्च 2026। अमेरिका-इजरायल की इंग के कारण पश्चिम एशिया में बने संघर्ष के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर्स की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, रेल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव समेत अन्य सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक में पूरा जोर देश में जरूरी संसाधनों की बिना रोक सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रिब्यूशन तय करने पर रहा। जिससे देश के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आज ही अमेरिका के टेक्सस से लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर एक कार्गो शिप मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। रूस से भी एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब पांच जहाज गैस-कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंच चुके हैं।

सप्लाई चैन और वितरण पर खास जोर

बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में ऊर्जा और उर्वरक की सप्लाई प्रभावित न हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सप्लाई चैन को मजबूत रखा जाए और देशभर में संसाधनों का सुचारु वितरण सुनिश्चित किया जाए।

हॉर्मूज स्ट्रेट पर असर, वैश्विक बाजार में हलचल

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस तनाव का असर हॉर्मूज स्ट्रेट के जरिए होने वाले व्यापार पर पड़ा है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है।



ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव से खिड़ते हालात

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और गहरा गई है।

डीजल की कीमतों में उछाल

संघर्ष के असर से ऊर्जा कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। औद्योगिक डीजल की कीमत करीब 25 फीसदी बढ़कर 87.67 रुपये प्रति लीटर से 109.59 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप गैस-कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके, फारस की खाड़ी में सभी 22 जहाज सुरक्षित

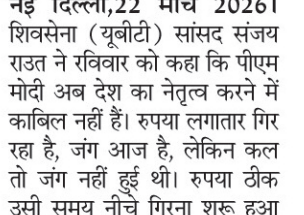
बंगलुरु, 22 मार्च 2026। अमेरिका के टेक्सस से लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर एक कार्गो शिप रविवार को मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया है। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब पांच जहाज गैस-कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर 'जग लाइव', गुजरात में अडाणी पोर्ट्स आया था। वहीं, दो अन्य एलपीजी केरियर एमटी शिवालिंक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे।



हालांकि, ये तीनों जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट के रास्ते से होकर गुजरे थे। फारस की खाड़ी में अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हालांकि, वे सभी सुरक्षित हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के अहम शिपिंग रूट्स में शामिल है। यहां से दुनियाभर की करीब 20% ऑयल की सप्लाई होती है। मंगलुरु में

भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज सुविधा भी है। यह स्टोरेज समुद्र तल से 225 मीटर नीचे स्थित है और इसकी क्षमता 80,000 मीट्रिक टन है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और रूस से लगातार आपूर्ति मिलने से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और घरेलू एलपीजी स्टॉक को बनाए रखना आसान होगा। इस पूरी स्थिति से यह साफ होता है कि युद्ध और वैश्विक संकट के बीच भी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है।

मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ, आप देश चलाने के काबिल नहीं, रुपया गिर रहा : राउत



नई दिल्ली, 22 मार्च 2026। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने में काबिल नहीं हैं। रुपया लगातार गिर रहा है, जंग आज है, लेकिन कल तो जंग नहीं हुई थी। रुपया ठीक उसी समय नीचे गिरना शुरू हुआ जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम अभी भी इलेक्शन कैम्पेन में बिजी हैं और उन्हें रुपये की कोई परवाह नहीं है। मेरे पास उनसे कहने के लिए बस एक ही बात है कि 'मोदी जी, अब झोला उठाओ और चले जाओ।' दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना एमपी ने कहा, अब रुपये के हालात देखिए।

बस संचुरी लगना बाकी है। अबकी बार, 100 के पार। बताइए मोदी जी कहाँ हैं? वे पश्चिम बंगाल में हैं, ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रेसिडेंट रूल की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी और शाह जी पश्चिम बंगाल में 'खेला' करने की कोशिश कर रहे हैं, और रुपये की वैल्यू गिर रही है।

कतर हेलिकॉप्टर क्रैश में तुर्की के मेजर समेत सात लोगों की मौत, लापता कैप्टन का शव बरामद

दोहा, 22 मार्च 2026। कतर में हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए सात में से तीन तुर्की नागरिक थे। दोहा ने रविवार को एक बयान जारी कर बताया कि मिलिट्री हेलिकॉप्टर हादसे में सात लोग मारे गए। तुर्की की ओर से भी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सशस्त्र बलों के एक सदस्य और तुर्की की डिफेंस कंपनी के दो तकनीशियनों के मारे जाने की पुष्टि की गई। बताया कि 21 मार्च की शाम को, कतर सशस्त्र बलों का एक हेलिकॉप्टर, जो कतर-तुर्की संयुक्त बल कमान के तलाबधान में प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित कर रहा था। समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया; प्रारंभिक जांच के अनुसार, ऐसा किसी तकनीकी खराबी से हुआ। तत्काल चलाए गए खोज और बचाव अभियानों के परिणामस्वरूप, हेलिकॉप्टर का मलबा और हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर बरामद किए गए। इसमें आगे बताया गया कि दुर्घटना में, कतर सशस्त्र बलों के चार कर्मी, तुर्की सशस्त्र बलों का एक सदस्य और एएसईएलएसएएन (अग्रणी रक्षा कंपनी) के दो तकनीशियन, जो हेलिकॉप्टर में सवार थे ने अपनी जान गंवा दी। दुर्घटना का निश्चित कारण कतर के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जाँच के बाद निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले, कतर के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान



जारी कर मृतकों के नाम बताए थे। बयान में कहा गया कि सुबह चले खोज और बचाव अभियानों के तहत, कतर सशस्त्र बलों के कैप्टन (पायलट) मुबारक सलेम दवाय अल-मारी, सर्जेंट फहद हदी गेनेम अल-खवारि, और कॉर्पोरल मोहम्मद माहेश मोहम्मद; कतर-तुर्की संयुक्त बलों के मेजर सिनान ताशतेकिन; और विमान के यात्रियों में शामिल तुर्की के नागरिक सहयोगी सुलेमान जेमरा कह्रामान और इस्माइल अनास कैन की मृत्यु हो गई। वहीं, कतर सशस्त्र बलों के लापता कैप्टन (पायलट) सईद नासिर समेख की खोज के लिए अभियान जारी रखा गया। दोपहर बाद पुष्टि की गई कि सातवां शव भी बरामद कर लिया गया है और वो लापता कैप्टन सईद नासिर समेख का ही है।

केसी त्यागी रालोद में शामिल... दिल्ली में जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता, वेस्ट की कई सीटों पर बदलेगे समीकरण

मेरठ, 22 मार्च 2026। वरिष्ठ राजनेता किशन चंद (केसी) त्यागी रालोद में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने उन्हें रालोद की सदस्यता दिलाई। नौवीं लोकसभा में हापुड़-गजियाबाद के सांसद रह चुके केसी त्यागी पिछले 26 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का हिस्सा थे। उनके रालोद में आने से वेस्ट यूपी की कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने नतीशा कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने के निर्णय के बाद जदयू को अलविदा कहने का फैसला किया। उनका मानना है कि बिहार तक सीमित जदयू में पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता के लिए भविष्य में कोई विशेष भूमिका नहीं रह जाती। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और आपातकाल के समय जॉर्ज



रालोद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य

रालोद, जो पारंपरिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित एक क्षेत्रीय दल रहा है, को चुनाव जीतने के लिए अक्सर अन्य दलों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। चौधरी चरण सिंह के बाद, उनके पुत्र चौधरी अजित सिंह और अब पौत्र जयंत चौधरी, जॉर्ज समुदाय के बीच वह मजबूत पकड़ बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं, जो चौधरी चरण सिंह के समय थी। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के टिकैत बंधुओं जैसे नेताओं ने भी इस विरासत में संघ लगाई है।

में बनाए रखने का एक प्रयास है, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी एक और पारी खेलने का संकेत भी देता है। केसी त्यागी के रालोद में शामिल होने से पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में रालोद भाजपा के गठबंधन में शामिल है और जयंत चौधरी मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में रालोद और भाजपा के मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, ऐसे में केसी त्यागी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

इन सीटों पर पड़ सकता है असर : मोदीनगर, मुगदनगर और सिवालखास जैसी सीटों पर, जहां भाजपा के साथ गठबंधन में रालोद का दावा कई वर्तमान विधायकों और भावी प्रत्याशियों का समीकरण बिगड़ सकता है। यह माना जा रहा है कि केसी त्यागी इन सीटों पर अपने करीबी लोगों को टिकेट दिलाने के लिए जोर लगा सकते हैं।

सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे, हजारों लोगों ने स्वागत किया बोले... उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे, एनएसए में जेल में बंद थे

लेह, 22 मार्च 2026। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक रविवार को 6 महीने (करीब 170 दिन) बाद लेह पहुंचे। केंद्र ने 14 मार्च को वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्किमिटी एक्ट हटाया था। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। लेह में उनके लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वांगचुक के सैकड़ों समर्थक पहुंचे। वांगचुक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा- जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए एक नया सूरज उगेगा। हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि 170 दिनों के बाद इन पहलुओं में आकर और लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है कि सभी तरफ से ऐसा ही माहौल बनेगा और मैं पूरे देश के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। मैं लोगों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।



कानूनी लड़ाई में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल, केंद्र ने 14 मार्च को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्किमिटी एक्ट हटाया था। पिछले साल लद्दाख में उनके अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हुई थी। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था। 170 दिन से वे जोधपुर जेल में थे। एनएसए सरकार को

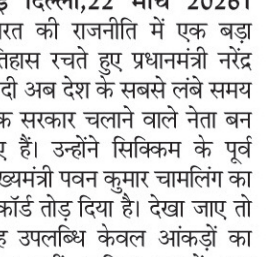
अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी की समझ पर प्रश्नचिह्न : शेखावत

जोधपुर, 22 मार्च 2026। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, इस पर ही प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री शेखावत रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान जब केंद्रीय मंत्री से राहुल गांधी के रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने और महंगाई बढ़ने से जुड़े ट्वीट के विषय में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं। ग्लोबल सिनेरियो है। अभी जिस तरह का जिओ टर्नलेंस विषय में है। जिस तरह की उथल-पुथल वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट युद्ध से बनी है। सोना की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी सोने को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। अभी रुपया को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने रचा इतिहास.. भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने



नई दिल्ली, 22 मार्च 2026। भारत की राजनीति में एक बड़ा इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखा जाए तो यह उपलब्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि दशकों तक लगातार नेतृत्व, जनसमर्थन और राजनीतिक स्थिरता की कहानी भी है। पीएम मोदी अब तक कुल 8931 दिन सरकार के मुखिया (हेड ऑफ गवर्नमेंट) के रूप में काम कर चुके हैं। इसमें उनका गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल शामिल है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जिन्होंने 8930 दिन तक सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी संभाली थी। पीएम मोदी की यह उपलब्धि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लंबे सार्वजनिक जीवन की जमकर सराहना की है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की दशकों की सेवा ने भारत में एक नया दौर शुरू किया है। उन्होंने गरीबों को अधिकार दिलाने, विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और दुनिया में भारत की छवि मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और पिछले 24 साल से अधिक समय से बिना छुट्टी लिए देश की सेवा कर रहे हैं। अमित शाह ने बताया कि पीएम मोदी को जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है।

संपादकीय

शिक्षा में चाहिए ज्यादा निवेश, 'स्टडी इन इंडिया' मिशन से क्या बदलेगी तस्वीर?

हर साल बढ़ी संख्या में भारतीय युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान सुविधाओं और करियर के अवसरों की तलाश में विदेश जाते हैं। अब 'स्टडी इन इंडिया' पहल के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 2,00,000 विदेशी छात्रों को आकर्षित करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य यह संकेत है कि भारत को केवल प्रतिभाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। हाल के कई रजिशन इस महत्वाकांक्षी को सार्थक बनाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 2023 में 9,00,000 से अधिक से घटकर वर्ष 2025 में लगभग 6,25,000 रह गई है। इसके कई कारण हैं। प्रमुख गंतव्य देशों, खासकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में आब्रजन नियमों में सख्ती आई है। वीजा जांच के अलावा वित्तीय लागत बढ़ गई है और अध्ययन के बाद रोजगार के रास्ते कम निश्चित हो गए हैं। कई छात्रों और परिवारों के लिए विदेशी शिक्षा पर निवेश का लाभ अब कुछ साल पहले की तुलना में कम निश्चित लगता है। भारत इस व्यवधान को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। लगभग 19 विदेशी विश्वविद्यालय देश में अपने परिसर स्थापित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक नीतिगत ढांचा अब अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भारत में या गिफ्ट सिटी जैसे विशेष क्षेत्रों में स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका तर्क सीधा है। यदि वैश्विक विश्वविद्यालय भारत में छिपे प्रदान कर सकते हैं, तो छात्र विदेश जाने के खर्च और अनिश्चितताओं के बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

साथ ही, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर एशिया, अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों के छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं। वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए आकर्षण स्पष्ट है। भारत में उच्च शिक्षा की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है और तृतीयक स्तर पर नामांकन आज के लगभग 5.3 करोड़ से बढ़कर 2035 तक 7 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। इसका तर्क सीधा है। यदि वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए आकर्षण स्पष्ट है, तो छात्र विदेश जाने के खर्च और अनिश्चितताओं के बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

साथ ही, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर एशिया, अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों के छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं। वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए आकर्षण स्पष्ट है। भारत में उच्च शिक्षा की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है और तृतीयक स्तर पर नामांकन आज के लगभग 5.3 करोड़ से बढ़कर 2035 तक 7 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है। इसका तर्क सीधा है। यदि वैश्विक विश्वविद्यालयों के लिए आकर्षण स्पष्ट है, तो छात्र विदेश जाने के खर्च और अनिश्चितताओं के बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

माटी अब भी पूछती

पैदा क्यों होते नहीं, भगत सिंह से वीर, माटी अब भी पूछती, कब जागेगी पीर? स्वप्न सिसकते रह गए, कहाँ गई वह बात, चिंगारी तो जल रही, राख हुई सागत। नारे मंच पर गुंजते, हुई जुवां है मौन, जोश बिखरकर रह गया, जज्बा लाये कोन। होते हैं भाषण बहुत, पर खामोश जमीर, शब्द बचे हैं युद्ध के, गए कहाँ रणधोर। भारत माता पूछती, कौन बने कुर्बान, सत्ताओं की साँकलें, बांध रही भूचाल। सत्ताओं की साँकलें, बांध रही तकदीर, खुद को खुद से हारकर, भारत खड़ा अधीर।

अफीम के खेत में उगा 'सरकारी धान', सिस्टम बोला-सब ठीक है!

कागज में धान, जमीन पर अफीम-सिस्टम की आंखों पर किसका पर्दा ?

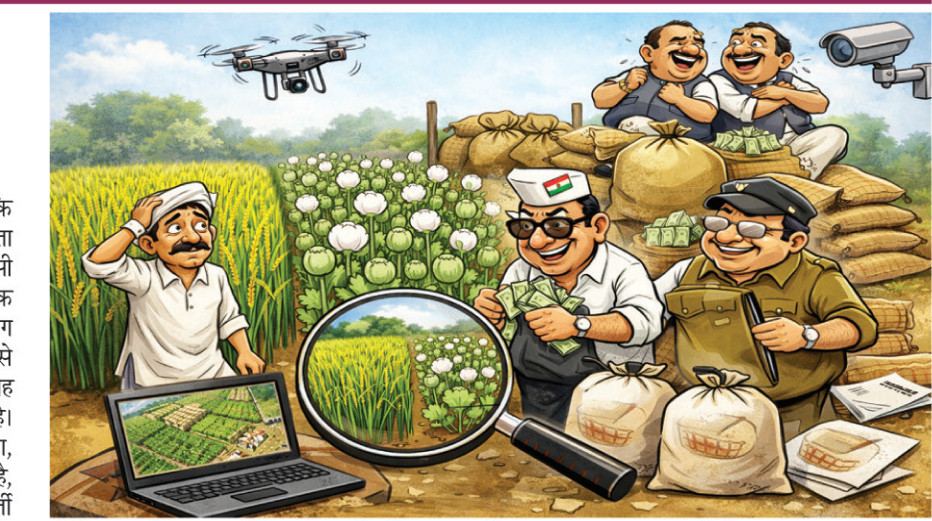
- अफीम की फसल, धान की रसीद - सरकार का खजाना किसने लूटा ?
■ जिओ-टैगिंग फेल या मिलीभगत का खेल ? अफीम खेत से धान खरीदी पर सवाल
■ जिस खेत में नशा उगा, वहाँ से निकला 'धान का पैसा' !
■ अफीम के खेत में उगा धान : व्यवस्था की आंखों पर पट्टी या मिलीभगत का खेल ?



रवि सिंह, वैकुण्ठपुर, कोरिया (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ में सामने आया 'अफीम बनाम धान' का मामला केवल एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल है, जिस खेत में अफीम जैसी अवैध फसल उगा रही थी, उसी खेत के नाम पर धान की फसल दर्ज हुई, सरकारी खरीद केंद्रों में बेची गई और भुगतान भी हो गया, यह घटना किसी एक व्यक्ति की भूल नहीं, बल्कि व्यवस्था की परतों में छिपी गंभीर खामियों का संकेत देती है। धान खरीदी की

प्रक्रिया में गिरदावली, जिओ-टैगिंग और डिजिटल सत्यापन जैसे कई स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की गई है, इनका उद्देश्य फर्जीबाई को रोकना और वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन जब रिपोर्टों में धान और जमीन पर अफीम दिखती है, तो यह विरोधाभास अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्या रिपोर्ट गलत बनाए गए या फिर जानबूझकर सच्चाई को नजरअंदाज किया गया? यह स्थिति बताती है कि या तो सिस्टम निष्क्रिय है या फिर उसे निष्क्रिय बना दिया गया है, सरकार ने पारदर्शिता के लिए तकनीक का सहारा लिया, लेकिन जब इतनी तकनीकी व्यवस्था के बावजूद ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं, तो सवाल तकनीक पर नहीं बल्कि उसे संचालित करने वाले मानव तंत्र पर उठता है, तकनीक कभी अपने आप गलत नहीं होती, उसका गलत उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है, इस मामले में भी यही



आशंका मजबूत होती है कि तकनीक केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, यह मामला किसी एक खेत या एक किसान तक सीमित नहीं लगता। अलग-अलग स्थानों से सामने आ रहे ऐसे उदाहरण यह संकेत देते हैं कि यह एक संगठित पैटर्न हो सकता है। यदि जिस खेत में धान नहीं उगा, वहाँ से भी धान खरीदी हो रही है, तो यह सीधे-सीधे फर्जी गिरदावली, फर्जी खरीदी और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है। यह सवाल भी उठता है कि ऐसा सब कुछ किसके संरक्षण में संभव हो पा रहा है। धान खरीदी प्रक्रिया में कई स्तरों पर निगरानी होती है पट्टवारी से लेकर जिला प्रशासन तक। इसके बावजूद यदि ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि या तो निगरानी केवल औपचारिकता थी या फिर जिम्मेदार लोग जानबूझकर आंखें मूंदे हुए थे। दोनों ही स्थितियाँ समान रूप से चिंताजनक हैं, अफीम की खेती स्वयं में एक

गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिसका संबंध नशे के अवैध नेटवर्क से होता है। ऐसे में जिस खेत में यह खेती हो रही थी, वहाँ प्रशासनिक चूक केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था की विफलता भी है। यह मामला केवल राजस्व या कृषि का नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी प्रश्न है, मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता को केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस जवाब और कार्रवाई चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस धान की फसल वास्तव में थी ही नहीं, उसका भुगतान किसने मिला और किस आधार पर मिला, जब तक इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तब तक यह पूरा प्रकरण अधूरा रहेगा, अब यह समय केवल जांच का नहीं, बल्कि सिस्टम सुधार का है, निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, तकनीक का सही उपयोग और फर्जी भुगतान की वसूली जैसे कदम उठाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि भविष्य में और बड़े घोटालों की भूमिका बन सकती है। यह मामला हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है, समस्या खेत में नहीं, बल्कि व्यवस्था में है, जब कागज पर धान उगता है और जमीन पर अफीम, तो यह संकेत है कि सिस्टम ने सच्चाई देखना बंद कर दिया है। अब आवश्यकता है उस सच्चाई को सामने लाने की, जिम्मेदारी तय करने की और जनता का भरोसा बहाल करने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आने वाले समय में यह सवाल और गुंजाणू, क्या इस व्यवस्था में सच कभी उगा भी था नहीं?

सूने हैं पनघट और प्यासे हैं पोखर-ताल

संस्कृत वांगमय का आंगन जल-माहात्म्य के श्लोकों एवं ऋचाओं से परिपूर्ण है। 'आपः वंदे मातरम्' कह कर प्राणिमात्र के पोषण के लिए जल को माता की भूमिका में स्वीकार कर श्रद्धा एवं सम्मान अर्पित किया गया है। लोक जीवन में जल वरुण देवता के रूप में पूजित एवं अर्चित है। हिंदू परम्परा में जन्म से मृत्यु पर्यंत समस्त कर्मकाण्ड जल के सान्निध्य में ही सम्पन्न होते हैं। नव प्रसूता द्वारा कुआँ पूजन की रस्म इसी रीति का आवश्यक अंग बनकर जीवन के सर्वांगीण विकास में जल की उपयोगिता पर लोक की ललित छाप ही है। किसी अनुष्ठान हेतु उदात्त यज्ञमान हथेली में कुश, अक्षत और जल लेकर ही संकल्पबद्ध होता है। तो सरिता एवं सरोवरों में स्नानोपरांत अंजुलि में जल लेकर कुआँ की अर्घ्य अर्पित कर लोक के योगक्षेम की कामना के मनोसारी दृश्य भी दिखते हैं। संस्कृत काव्य का प्रथम छंद प्रब्रह्ममन सरिता-नीर के जल मय ही ऋषि वाल्मीकि के मुख से उच्चरित हुआ था। जल का अर्घ्य देकर ही देवता और अतिथि के अर्चन, वंदन एवं सत्कार करने की हमारी शाश्वत परम्परा अनवरत गतिमान है। जल ही रक्त का रूप धारण कर हमारी देह में दौड़ रहा है। जल जीवन का पर्यय है, जल मानवीय अस्तित्व, अस्मिता और गौरव का आधार है। जल मर्यादा का विन्ध बनकर उभरा तो पौरुष, शौर्य और पराक्रम का सुदृढ़ स्तम्भ भी। तभी तो किसी के अयोध्यादि कर्म पर कहा गया कि उसके आँख का पानी भर गया है और युद्ध के लिए एक-दूसरे को चुनौती देने में कहेते हैं कि देह में पानी बचा हो तो मैदान में आओ। इतना ही नहीं, प्राणिमात्र की उत्पत्ति भी जल में ही हुई है। मानव सभ्यताएँ जल के स्रोतों-संसाधनों के आसपास ही विकसित हुईं, इसीलिए उन्हें नदी-घाटी सभ्यता कहा जाता है। पर अति आधुनिकता के दौर में भोगवादी मूल्य में बैठा मानव जल को केवल उपभोग की वस्तु समझ केवल वर्तमान जो रहा है। उसे बिल्कुल धान नहीं है कि उसके पैरों के नीचे की नमी सूख चुकी है।

और यह नमी का सूखना दरअसल मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों का सूखना-छीनना है। प्रकृति और मानव के परस्पर आत्मीय सम्बन्धों का निर्जल एवं रसहीन हो जाना है। ऐसे रसहीन जीवन में कुट्ट, घृणा, हिंसा, अमानवीयता तो सम्भव है पर श्रेय, माधुर्य, शौच, सौंदर्य, समता, सद्भाव, अहिंसा एवं प्रति का अजस स्रोत सम्भव नहीं। भले ही आज की पीढ़ी ने जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन से दूरी बना मुह मोड़ लिया हो पर हमारे पूर्वजों ने जल संसाधनों के रूप में कुआँ, तालाब, पोखर, बावड़ी आदि न केवल निर्मित किए बल्कि उनको समाज का एक जरूरी हिस्सा मानकर संवर्धन एवं संरक्षण के लगातार उपाय भी करते रहे हैं। इसीलिए तालाब-कुएँ खुदवाना पुण्य का क्षेत्र माना गया और जो समर्थनयन थे वे नैतिक दृष्टि से कपड़े धोना बर्जित था। नदियाँ माँ समान थीं, तभी श्रम क्लान्त और आतप से तप्त देह शीतल सरिता जल में अवगाहन कर पुनःनवल ऊर्जा एवं उत्साह संचो लेती। तुषित पथिक पद प्रक्षालन कर थकान मिटा अंजुलि भर जल पान कर तृप्त हो स्वच्छ निर्मल जल के सतत प्रवाह की प्रभु से प्रार्थना करता। पर समय कहीं चरता है। समय अपनी गति चलता रह, पीढ़ियाँ बदलती रहीं और बदलती रहीं सोच, दृष्टि एवं जल-दर्शन की सांस्कृतिक परम्परा। फलतः जल के माहात्म्य से दूरी भनी और एक संकट सामने उपस्थित हुआ। यह संकट मानव की भोगवादी एवं अप्राकृतिक जीवन शैली से उपजा है। संकट की विकाराता का ही परिणाम है कि सम्पूर्ण विश्व में जल के प्रति जागरूकता, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की पहल करनी पड़ी। विश्व के सामने एक गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित जल संकट के प्रति हम जागरूक होकर जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान देने की बजाय पानी की बर्बादी और संसाधनों को नष्ट होते देख रहे हैं, मौन हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक अंकड़े के अनुसार 3-4 अरब लोग प्रत्येक वर्ष एक महीने के लिए पानी की उपलब्धता की भागी कर्मी से गुजरते हैं। विश्व के सभी देशों में सभी नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध

कराने, जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता का प्रसार करने और जल के समुचित उपयोग करने के लिए 1992 में रियो डि जेनेरियो (ब्राजील) में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण एवं विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मना कर संयुक्त विश्व का ध्यान इस गंभीर संकट की ओर खींचा गया। तब से प्रत्येक वर्ष एक थीम आधारित आयोजन पूरे विश्व में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर संचालित किए जाते हैं, जिसमें स्कूल-कॉलेज में जल संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएँ याद-विवाद, भाषण, परिचर्चा, चित्र बनाना, पोस्टर निर्माण एवं वृत्तचित्र के द्वारा आम जन को जल के भयावह संकट से परिचित कराने का प्रयास किया जाता है। उल्लेखनीय है कि हमारी पृथ्वी का तीन-चौथाई भाग जल से ढंका हुआ है। धरती पर उपलब्ध जल का 99 प्रतिशत सागर एवं महासागरों में है। केवल एक प्रतिशत जल ही उपयोग के मितले, कुड़ा-कचरे का नदियों-सरोवरों में उडेलने शहरीकरण एवं कंक्रीट की चादर बिछते जाने से वर्ष जल का धरती की कोख में न समाकर व्यर्थ बह जाने, विभिन्न उद्योगों में प्रचुरता से प्रयोग करने आदि से यह संकट उपजा है।

अमेरिका-ईरान-इजराइल महायुद्ध... युद्ध विराम के लिए भारत होगा संभावित विकल्प

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। विशेषकर तब जब दुनिया लगातार संघर्षों की आग में झुलस रही है, रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और अब अमेरिका-इजरायल-ईरान महायुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं अपेक्षित प्रभाव खोती जा रही हैं। कभी विश्व राजनीति का केंद्र माने जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र संघ अब कई बार केवल औपचारिक बयानबाजी तक सीमित दिखाई देता है, युद्धविराम के प्रयास या तो बहुत देर से होते हैं या फिर प्रभावहीन सिद्ध होते हैं, यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली आज के समय के अनुरूप है भी या नहीं, क्योंकि स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार ने कई बार निर्णय प्रक्रिया को जकड़ कर रखा है। परिणामस्वरूप शक्तिशाली देशों के हितों के आगे सामूहिक शांति प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, इस संदर्भ में यह धारणा भी बलवती हुई है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रभाव इस संस्था पर अत्यधिक है उसे अमेरिका का पिछलग्वाण कहा जाता है जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। ऐसे जटिल वैश्विक समीकरणों के बीच भारत एक संतुलित और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की विदेश नीति का मूल आधार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवतु सुखिनः' जैसे सिद्धांत रहे हैं, यही कारण है कि भारत ने कभी भी किसी एक ध्रुव का समर्थन करने के बजाय संवाद और कूटनीतिक को प्राथमिकता दी है। चाहे संबंध अमेरिका से हों या रूस से, चाहे इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी हो या ईरान के साथ ऊर्जा और सांस्कृतिक रिश्ते, भारत ने हर दिशा में संतुलन बनाए रखा है, यही संतुलन आज उसे वैश्विक माध्यम की भूमिका के लिए उपयुक्त व बेहतर विकल्प बनाता है। वर्तमान परिस्थिति में जब पश्चिमी देश एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं और कई इस्लामी देश दूसरी तरफ, तब भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आता है जिसके पास सभी पक्षों से संवाद करने की क्षमता और विश्वास दोनों हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के साथ भी भारत की साझेदारी मजबूत है, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक सहयोग और विकासवादी भागीदारी उसे एक व्यापक वैश्विक प्रतिनिधि बनाती है, यही कारण है कि आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठ रहे हैं तब भारत को एक संभावित विकल्प या कम से कम एक प्रभावी पूरक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि किसी एक देश के लिए पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना आसान नहीं है, भारत की अपनी सीमाएँ हैं, उसकी प्राथमिकताएँ हैं और उसकी आंतरिक चुनौतियाँ भी हैं, फिर भी भारत ने समय-समय पर शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे शांति सैनिकों की तैनाती हो या मानवीय सहायता, भारत हमेशा अग्रणी रहा है, वर्तमान संकट में भारत यह सक्रिय कूटनीतिक पहल करता है, तो यह सहायक के नए रास्ते खोल सकता है। बैक-चैनल वार्ता, बहुपक्षीय बैठकें और क्षेत्रीय शांति सम्मेलन जैसे उपाय भारत के माध्यम से संभव हो सकते हैं, इसके साथ ही भारत का जी-20 जैसे मंचों पर नेतृत्व अनुभव भी उसे वैश्विक सहमति बनाने में मदद करता है, लेकिन यह अपेक्षा करना कि भारत तुरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की विकल्प बन जाए, शायद व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की संरचना, वैधता और वैश्विक स्वीकृति अभी भी अद्वितीय है, आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे उभरते शक्तिशाली राष्ट्र इस संस्था में सुधार की दिशा में नेतृत्व करें, सुरक्षा परिषद का विस्तार, वीटो प्रणाली में बदलाव और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी जैसे कदम इस संस्था को पुनः प्रासंगिक बना सकते हैं, अंततः यह कहना जा सकता है कि आज की दुनिया एक नए संतुलन की तलाश में है।



संजीव ठाकुर, राजीवपुर, छत्तीसगढ़

महान वैज्ञानिक पियरे-साइमन लाप्लास पर विशेष



संजय गोस्वामी, अनुसूचितनगर, मुंबई

पियरे-साइमन लाप्लास का जन्म 23 मार्च 1749 को ब्यूमान्त-एन-ऑज, नॉर्मंडी, फ्रांस में हुआ। पियरे-साइमन लाप्लास ने सौर मंडल की स्थिरता को सिद्ध किया। विश्लेषण में लाप्लास ने पोटेंशियल फंक्शन और लाप्लास गुणांक पेश किए। उन्होंने गणितीय प्राथिकता के सिद्धांत को भी एक ठोस आधार दिया। लाप्लास की माँ, मैरी-एनी सोशोन, एक काफी समृद्ध किसान परिवार से थीं, जिनकी दूरगोविले में जमीन थी। लाप्लास ने 7 से 16 साल की उम्र के बीच ब्यूमान्त-एन-ऑज में एक बेनेडिक्टिन प्रायरी स्कूल में एक डे-स्टूडेंट (दिन के छात्र) के रूप में पढ़ाई की। उनके पिता चाहते थे कि वे चर्च में अपना करियर बनाएँ, और सच तो यह है कि प्रायरी स्कूल के छात्रों के लिए चर्च या सेना ही आमतौर पर करियर के मुख्य रास्ते होते थे। 16 साल की उम्र में लाप्लास ने केन्यूनिवर्सिटी में

दाखिला लिया। पेरिस में उन्होंने डी'अलेम्बर्ट के नाम एक परिचय पत्र (सिफारशी पत्र) ले गए। हालाँकि जब लाप्लास पेरिस पहुँचे, तब उनकी उम्र केवल 19 साल थी, फिर भी उन्होंने बहुत जल्द डी'अलेम्बर्ट को प्रभावित कर दिया। डी'अलेम्बर्ट ने न केवल लाप्लास की गणितीय पढ़ाई को निर्देशित करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने लाप्लास के लिए एक ऐसी नौकरी खोजने की भी कोशिश की जिससे वह पेरिस में अपना गुजारा करने लायक पैसे कमा सके, पी ए च डी करने के बाद जल्द ही लाप्लास को कले मिलितरे में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। वैज्ञानिक गिलेस्पी लाप्लास के बारे में लिखते हैं:- वे अच्छे परिवारों से आए, औसत दर्जे की पढ़ाई वाले और विषयों के प्रति कोई खास लगन न रखने वाले किशोर कैडेटों को ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक विश्लेषण और स्टैटिस्टिक पढ़ाना लाप्लास के लिए एक खास प्रेरणादायक काम नहीं था, लेकिन इस पद की वजह से लाप्लास पेरिस में रह पाए। 28 मार्च 1770 को पेरिस में एकेडेमी डेस साइंसेज के समक्ष कलन पर शोध पत्र, प्रस्तुत किया। यह पहला पत्र, जो सोसायटी में पढ़ा गया परंतु प्रकाशित नहीं हुआ, वहाँ के अधिकतम और न्यूनतम पर था, जहाँ उन्होंने लैंग्रेंज द्वारा दिए गए तरीकों में सुधार किया। एकेडेमी के लिए उनका अगला शोध-पत्र इसके तुरंत बाद आया, और 18 जुलाई 1770 को उन्होंने 'डिफरेंस इक्वेशंस' (अंतर समीकरणों) पर एक शोध-पत्र पढ़ा। लाप्लास का पहला पेपर जो

छपा, वह इटीग्रल कैलकुलस पर था, जिसे उन्होंने लैटिन में ट्रांसलेट किया और 1771 में लाइपनिंग में नोवा एक्टा एरिडिटोरम में प्रकाशित किया। छह साल बाद लाप्लास एक बेहतर वर्शन फिर से प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 1771 के पेपर के लिए माफ़ी माँगी और उसमें मौजूद गलतियों के लिए प्रिंटर को जिम्मेदार ठहराया। लाप्लास ने मैक्सिमा और मिनिमा पर पेपर का लैटिन में अनुवाद किया और इसे 1774 में नोवा एक्टा एरिडिटोरम में प्रकाशित किया। इसके अलावा 1771 में लाप्लास ने एक और पेपर रेचेचेंस सुर ले कैल्क्युल इटीग्रल ऑक्स डिफरेंसिएस इन्फिनिमीमेंट पेटिटस, एट एकेडेमी डेस साइंसेस में चुनाव जीतने की पहली कोशिश की, लेकिन वेडमोडे को प्राथमिकता दी गई। लाप्लास ने 1772 में फिर से सदस्यता देने की कोशिश की, लेकिन इस बार कजिन को चुन लिया गया। उस समय लाप्लास की उम्र केवल 23 वर्ष थी (जबकि कजिन 33 वर्ष के थे)। इसके बावजूद, जब उन्हें नजरअंदाज करके एक किंग एंसे गणितज्ञ को चुना गया जो स्पष्ट रूप से उनसे कई कमतर दर्जे का था, तो लाप्लास को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। 31 मार्च 1773 को उन्हें एकेडेमी डेस साइंसेस में 'एडजॉइंट' (सहायक सदस्य) के रूप में

महसूस होने लगा था कि लाप्लास तेजी से उनके (डी'अलेम्बर्ट के) जीवन भर के कार्यों को अप्रचलित बनाते जा रहे हैं; और इस बात से उनके आपसी संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ। लाप्लास ने डी'अलेम्बर्ट के कार्यों के महत्व पर जोर देकर उनके कष्ट को कम करने का प्रयास किया, क्योंकि वे निस्संदेह डी'अलेम्बर्ट के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे-विशेषकर उस सहायता और समर्थन के लिए जो डी'अलेम्बर्ट ने उन्हें प्रदान किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि लाप्लास अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को लेकर बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे, और संभवतः वे अपने सहकर्मियों पर अपने इस रवैये के पड़ने वाले प्रभाव को समझने में असफल रहे। लेक्सैल ने 1780-81 में पेरिस स्थित 'एकेडेमी डेस साइंसेस' का दौरा किया और बताया कि लाप्लास ने यह बात खुलकर और व्यापक रूप से जाहिर कर रखी थी कि वे स्वयं को फ्रांस की सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ मानते हैं। 1780 में, अपने द्वारा आभिव्यक्त किए गए एक आइस कैलेरीमीटर की मदद से, यह दिखाया कि श्वसन भी एक प्रकार का दहन है। हालाँकि लाप्लास जल्द ही गणितीय खगोल विज्ञान के अपने अध्ययन पर लौट आए, लेकिन लेवोइसियर के साथ किए गए इस काम ने लाप्लास के लिए अनुसंधान के एक तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र की शुरुआत की-विशेष रूप से भौतिकी में उनका काम, और उसमें भी विशेष रूप से ऊष्मा के सिद्धांत पर, जिस पर उन्होंने अपने करियर के अंतिम दौर में काम किया।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी भी भावनाओं को डेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अभिव्यक्ति न्यायालय के अधीन होगा। -सम्पादक

संजय पार्क में आवारा कुत्तों का हमला, 15 हिरणों की मौत

फेंसिंग टूटी, रात में घुसे श्वान; लापरवाही पर 5 कर्मचारी निलंबित



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

शहर के संजय पार्क में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शनिवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच जंगल की ओर से आए आवारा कुत्ते पार्क परिसर में घुस गए और फेंसिंग के अंदर मौजूद हिरणों पर हमला कर दिया। इस हमले में 15 हिरणों की मौत हो गई। शनिवार सुबह जब पार्क कर्मचारियों ने निरीक्षण किया, तो 14 हिरण मृत अवस्था में पड़े मिले, जबकि एक गंभीर रूप से घायल था। सभी के शरीर पर कुत्तों के हमले के गहरे निशान पाए गए। घायल हिरण ने रविवार

को दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पार्क की बाउंड्री का तार एक जगह से पहले से टूटा हुआ था। इसी रास्ते से कुत्ते अंदर घुसे और घटना को अंजाम दिया।

पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पंचनामा तैयार कर वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अजीत पांडेय व डॉ. शैरी की टीम ने सभी मृत हिरणों का पोस्टमार्टम किया। जांच के लिए सैंपल और विस्तर सुरक्षित रखा गया। इसके बाद सभी हिरणों का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया।



कई प्रजातियों के हिरण मरे

मृत हिरणों में 5 मादा वीतल, 1 नर वीतल, 5 मादा कोटरा, 1 नर कोटरा और 3 नर चौंसिया शामिल हैं।

लापरवाही पर 5 कर्मचारी सस्पेंड

जांच में रात्रिकालीन ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। उप वनक्षेत्रपाल अशोक सिन्हा, वनपाल ममता पार्वी, वनपाल प्रतीमा लकड़ा, वनपाल विंदू सिंह और वनरक्षक फूलमनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अब सिर्फ 16 हिरण शेष

डीएफओ के अनुसार, पहले पार्क में 31 हिरण थे, लेकिन इस घटना के बाद अब संख्या घटकर 16 रह गई है।

सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

वन विभाग ने पूरे पार्क को सैनिताइज करने, फेंसिंग की मरम्मत कराने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

भर्ती परीक्षा कानून का भाजयुमो ने किया स्वागत

गड़बड़ी पर सख्ती, एक करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में नया कानून पारित किया गया है। जो प्रदेश की विद्युत् देव साय सरकार का युवाओं के लिए एक बड़ी पहल माना जा रहा है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिह के आह्वान पर भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिंसोदिया की उपस्थिति में अध्यक्ष निशांत सिंह शोल् के साथ भाजयुमो सरगुजा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने संभागीय सरगुजा ओलंपिक के शुभारंभ में पथारे मुख्यमंत्री विद्युत् देव साय को आभार पत्र देकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि नए कानून के तहत अब भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में घोटेला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकल कराने वाले गिरोह, फर्जी अभ्यर्थी या तकनीकी उपकरणों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले दोषियों को कड़ी सजा और अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून बनने से भर्ती प्रक्रिया में

पारदर्शिता को सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साय सरकार में युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एवं सरकार ने इस कानून के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसे सभी प्रमुख भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं पर लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम और विभिन्न निगम-मंडलों द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी शामिल होंगी। इस दौरान मुख्य रूप से भाजयुमो प्रदेश मंत्री प्रिया सिंह, भाजयुमो जिला महामंत्री अनोशी सिंह एवं अविनाश मंडल, उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चक्रधारी, शुभम अम्बिकापुर, रवजोत सिंह, शुभम भदौरिया, अंशुमल गर्ग, अनुराग शुक्ला, राहुल अग्रवाल, रितेश यादव, ओमकारेश्वर सिंह, कोशलदेव गुप्ता, प्रो. प्रो. प्रो. अम्बिका सिंह, अधिपेक माधुर, शैलेंद्र चौबे, प्रिंस तिवारी, आनंद साहू, समीर बेहरा, आनंद मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सुधांशु चौबे, आर्युष दुबे, विशाल सिंह, अमित अग्रवाल, रोहन मंडल, अधिपेक पावले, धर्मंद गुप्ता, संजय बेहरा, रमेश यादव, नर सिंह, लालू यादव, पांसनाथ यादव, नरेंद्र कुमार सारथी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दीपक बैज 23 मार्च को सरगुजा दौरे पर

बूथ व ग्राम कमेटीयों के गठन को लेकर कार्यक्रम तय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

कांग्रेस के संगठन सुजन अभियान के तहत प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज 23 मार्च को सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ग्राम, वार्ड और बूथ कमेटीयों के गठन के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बताया कि

बैज दोपहर 2 बजे बलौली के बोदा गांव में ग्राम व बूथ कमेटी गठन करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे लुंडा के बटवाही में बैठक लेंगे। वहीं शाम 6 बजे अम्बिकापुर के रामानुज वार्ड में वार्ड और बूथ कमेटीयों का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद प्रदेशाध्यक्ष अम्बिकापुर रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और 24 मार्च को प्रस्थान करेंगे।



कृषि मंत्री श्री रामविचार ने 52 करोड़ से अधिक राशि के 24 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

सड़क, पुल-पुलिया निर्माण से लोगों को मिलेगी बेहतर आवागमन सुविधा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : कृषि मंत्री नेताम



-संवाददाता-
बलरामपुर, 22 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति विकास, कृषि विकास एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत लिलौटी में आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 15 करोड़ 45 लाख 95 हजार रुपये की लागत के साथ सड़क निर्माण कार्य, पीएम जनपन योजना के तहत 34 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से 10 मार्गों में वृहद पुल-पुलिया का निर्माण तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडल बोर्ड के अंतर्गत 1 करोड़ 78 लाख रुपये की लागत से 7 कार्यों, कुल 52 करोड़ 7 लाख 71 हजार के 24 कार्यों का भूमिपूजन/शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के 11 पंचायतों के 11 कीर्तन मंडलियों को स्वेच्छानुदान के तहत 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निरकुंज, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री आमप्रकाश जायसवाल,

पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कृष्णा गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंहदेव, जनपद अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेवरा, उपाध्यक्ष श्रीमती बबली देवी, नगरपालिका अध्यक्ष श्री लोधीराम एक्का, जिला पंचायत सदस्य श्री मुंशी राम, बंदी यादव, श्रीमती अनिता मरकाम, ग्राम लिलौटी के सरपंच श्री देवनाथराय सिंह सहित क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी व बड़ी संख्या में ग्रामीजन मौजूद रहे। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा माना जाता था। यहां चलने के लिए ना पक्की सड़कें थीं, ना पुल-पुलिया और ना ही पेयजल एवं बिजली और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं। हमारी सरकार ने सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर योजनाबद्ध तरीके से प्रस्ताव तैयार कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। जनता के सहयोग से आज निरंतर इन लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब को अपना पक्का



मकान मिले, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें लाभांशित किया जा रहा है। साथ ही विद्युत् विहीन क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर वहां निर्बाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतिथ्य व्यक्तित्व तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य के तहत आज 52 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों की नींव रखी गई है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य तय समय-सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

इस दौरान कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं से विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ-साथ जैविक और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की बात कही। उन्होंने धान के साथ दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने की भी प्रेरित किया। उन्होंने किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए किसानों को दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और बकरी पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसान कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। पिछड़ा वर्ग आयोग के

सदस्य श्री कृष्णा गुप्ता ने कहा कि आज क्षेत्र के लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है कि 52 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मिली है। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में सड़कों, पुल एवं पुल-पुलियों का निर्माण होगा, जिससे आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी तथा आमजन को बेहतर परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री आमप्रकाश जायसवाल ने कहा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाना क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से निश्चित रूप से ग्रामीणों को सौधा लाभ मिलेगा। सड़कों, पुल-पुलियों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि गांवों की तस्वीर भी बदलेगी और आमजन का जीवन स्तर बेहतर होगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंहदेव ने कहा कि मंत्री श्री नेताम के द्वारा क्षेत्र को सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण में अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। पिछड़ा वर्ग आयोग के

सरगुजा ओलंपिक 2026 : दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, समापन समारोह में बाईचुंग भूटिया होंगे शामिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 22 मार्च 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर आयोजित तीन दिवसीय संभाग स्तरीय 'सरगुजा ओलंपिक' के दूसरे दिन खेल मैदानों पर उत्साह और रोमांच का माहौल रहा। जिला स्तर की बाधाएं पार कर पहुंचे खिलाड़ियों अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों से आए खिलाड़ियों ने न केवल मेडल की दौड़ में अपनी जगह बनाई है, बल्कि अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया है।

हॉकी के मैदान में जशपुर की बेटियों का जलवा

महिला हॉकी के मुकाबलों में जशपुर जिले की टीम ने तकनीकी कौशल और स्टीक तालमेल के दम पर शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम की कप्तान सुश्री सुप्रिया तिग्गा ने इस मंच के लिए शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल के ट्राइबल बच्चों को अपनी छिपी हुई प्रतिभा निखारने के लिए यह एक शानदार मंच मिला है। खेलों से न केवल हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि हम



अनुशासन सीखते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं। सरगुजा ओलंपिक ने हमारी प्रतिभा को संवारने का बड़ा अवसर दिया है।

बास्केटबॉल कोर्ट पर दिखा खिलाड़ियों का समन्वय : बास्केटबॉल खेलने आई महिला खिलाड़ियों ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शासन ने एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहाँ अलग-अलग जिलों के खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं आगे बढ़ेंगी। 12 खेल विधाओं में

आयोजित सरगुजा ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग (पुरुष) में गोविंद गुप्ता (जशपुर) ने प्रथम, सईल अंसारी (सूरजपुर) ने द्वितीय तथा अधिपेक करण (बलरामपुर) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (पुरुष) में टी. नाग. उमेशवर राव (एमसीबी) प्रथम, जितेंद्र चौधरी (बलरामपुर) द्वितीय तथा शेर सिंह (सरगुजा) तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में 17 वर्ष से कम आयु में रिया तिकी (जशपुर) प्रथम, संजना सिंह (सूरजपुर) द्वितीय तथा बबिता (बलरामपुर) तृतीय स्थान पर रहीं, जबकि 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में अंजु

सिंह (सूरजपुर) प्रथम, अंकिता यादव (एमसीबी) द्वितीय तथा अनोषा पन्ना (जशपुर) तृतीय स्थान पर रहीं। 200 मीटर दौड़ में 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (पुरुष) में अरुण कुमार (अम्बिकापुर) प्रथम, राकेश एक्का (जशपुर) द्वितीय तथा नीतिश कुमार (सूरजपुर) तृतीय स्थान पर रहे। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग (महिला) में सिमरन सिंह (कोरिया) प्रथम, संगीता (सूरजपुर) द्वितीय तथा निर्मला (बलरामपुर) तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (महिला) में स्नेहा (कोरिया) प्रथम, सुमन (एमसीबी) द्वितीय तथा मानती (सूरजपुर)



तृतीय स्थान पर रहीं। 400 मीटर दौड़ में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग (पुरुष) में यदुवंश (कोरिया) प्रथम, इंद्रजीत (सरगुजा) द्वितीय तथा रुपेश चौहान (जशपुर) तृतीय स्थान पर रहे। 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (पुरुष) में विश्वनाथ तिग्गा (जशपुर) प्रथम, सुनील कुमार (बलरामपुर) द्वितीय तथा योगेंद्र सिंह (सूरजपुर) तृतीय स्थान पर रहे। महिला वर्ग में 17 वर्ष से अधिक आयु में प्रज्ञा राजवाड़े (सूरजपुर) प्रथम, अंकिता राजवाड़े (कोरिया) द्वितीय तथा लक्ष्मी सिंह (सरगुजा) तृतीय स्थान पर रहीं, जबकि 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में रिया (सूरजपुर)

प्रथम, सुरोमी बाई (जशपुर) द्वितीय तथा प्रमिला (कोरिया) तृतीय स्थान पर रहीं। खबर लिखे जाने तक अन्य खेलों के परिणाम प्राप्त होना शेष था।

समापन समारोह में शामिल होंगे दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया

संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का समापन समारोह अत्यंत गरिमामय होगा। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और खेल जागत के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री बाईचुंग भूटिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

कागज पर तबादला, जमीन पर खेल : पीडब्ल्यूडी सूरजपुर में 'पोस्टिंग का प्रबंधन' या 'प्रबंधन की पोस्टिंग' ?

पीडब्ल्यूडी सूरजपुर में 'तिगड़ी राज': तबादले से लेकर सड़क तक सेटिंग का खेल उजागर

- कागज पर तबादला, जमीन पर सौदा, सूरजपुर पीडब्ल्यूडी में सिस्टम या सिडिकेट ?
- सड़क निर्माण या सप्लाई का खेल ? सूरजपुर पीडब्ल्यूडी में 'तिगड़ी' की पकड़ मजबूत
- तबादला, अवकाश और प्रभारी का खेल, पीडब्ल्यूडी सूरजपुर में अंदरखाने की सच्चाई
- सड़क कम, नेटवर्क ज्यादा पक्का : सूरजपुर पीडब्ल्यूडी में सेटिंग से तय हो रही गुणवत्ता
- पीडब्ल्यूडी में 'इनसाइड गेम': तबादले से लेकर मटेरियल सप्लाई तक सब तय!
- तिगड़ी का दबदबा या सिस्टम फेल ? सूरजपुर पीडब्ल्यूडी में उठे बड़े सवाल
- कागजों में विकास, जमीन पर खेल : सूरजपुर पीडब्ल्यूडी की परतें खुलीं
- प्रभारी पोस्टिंग से सप्लाई सिडिकेट तक : पीडब्ल्यूडी सूरजपुर में बड़ा खुलासा
- जहां सड़क बननी थी, वहां 'सेटिंग' बन गई: सूरजपुर पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप

-शमरोज खान-

सूरजपुर, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

लोक निर्माण विभाग सूरजपुर इन दिनों सुविधियों में है कारण सड़क निर्माण नहीं, बल्कि विभाग के भीतर चल रही कथित 'सेटिंग', 'तबादला राजनीति' और 'सप्लाई सिडिकेट' की चर्चाएं हैं, कागजों में सब कुछ नियमों के अनुसार दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत एक अलग कहानी बयां कर रही है। बात दे की सरकारी फाइलों की दुनिया बड़ी दिलचस्प होती है, यहाँ सब कुछ नियमों के मुताबिक होता है, लेकिन असल कहानी नियमों के पीछे छिपी होती है, ऐसा ही एक मामला लोक निर्माण विभाग सूरजपुर में सामने आया है, जहाँ 20 फरवरी 2026 को जारी तबादला आदेश ने कागजों पर तो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का रूप लिया, लेकिन जमीन पर इसकी परतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। तबादला: कागजों में सामान्य, चर्चा में खास-छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश में अनुविभागीय अधिकारी राजीव कुमार वर्मा का स्थानांतरण कर उन्हें अन्य पदस्थापना दी गई, जबकि उनकी जगह हेमंत कुमार एक्का को सूरजपुर भेजा गया, कागजों में सब कुछ एकदम दुरुस्त न कोई विवाद, न कोई सवाल, लेकिन जैसे ही फाइल दफ्तर से बाहर निकली, कहानी ने कण्ठ लेना शुरू कर दिया।

इनसाइड स्टेरी: 'भैल

नहीं खाया, तो खेल बनाया?'

सूत्रों की मानें तो यह तबादला महज रूटीन प्रक्रिया नहीं था, बल्कि विभागीय 'रिश्तों की केमिस्ट्री' का नतीजा था, चर्चा है कि राजीव कुमार वर्मा और सूरजपुर पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता के बीच तालमेल ठीक नहीं था, सरकारी भाषा में इसे 'कार्य में असंतोष' कहा जाता है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे सीधा कहा जा रहा है साहब से सेटिंग नहीं बेटी, तो सीट ही बकल दी गई।

नई पोस्टिंग, लेकिन अधिकारी गायब !

अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है, जिन हेमंत कुमार एक्का को सूरजपुर भेजा गया, वे एक महीने बाद भी ज्वाइन नहीं कर

पाए, यानी, कुर्सी खाली... और कुर्सी के आसपास राजनीति पूरी चालू, सवाल यह उठता है कि जब नया अधिकारी आया ही नहीं, तो पुराना अधिकारी क्यों हटाया गया? क्या इतनी जल्दी थी कि कुर्सी पहले खाली करनी जरूरी थी?

'अवकाश' का एंगल: कहानी या बहाना?

इसी बीच 10 मार्च 2026 को एक और आदेश जारी होता है, इसमें बताया जाता है कि राजीव कुमार वर्मा अपने पिता के स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर जा रहे हैं, अब यहाँ से कहानी में 'फिल्मी ट्विस्ट' आता है, सूत्रों का दावा है कि यह अवकाश 'स्वाभाविक कम, व्यवस्थागत ज्यादा' है, यानी सवाल यह की क्या अवकाश पहले तय था या बाद में बनाया गया?

प्रभारी का खेल: असली सेटिंग यहीं!

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हेमंत कुमार एक्का के ज्वाइन न करने की स्थिति में, उप अभियंता कल्याण सिंह पोते को प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी बना दिया गया, अब यहाँ असली सवाल उठता है, क्या यह पूरी प्रक्रिया पहले से तय थी? क्या किसी खास व्यक्ति को जिम्मेदारी दिलाने के लिए पूरा ट्रांसफर-ड्रामा रचा गया? क्योंकि नया अधिकारी आया नहीं, पुराने को अवकाश पर भेज दिया गया और तीसरे को प्रभारी बना दिया गया, इसे ही प्रशासनिक भाषा में कहते हैं—तीन चाल में मात।

ईई की भूमिका पर उठते सवाल

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कार्यपालन अभियंता की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि विभागीय समीकरण बिगड़े और विरोधी अधिकारी को हटाया गया और अनुकूल व्यवस्था तैयार की गई, हालांकि आधिकारिक तौर पर सब कुछ नियमों के तहत बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नियमों का उपयोग व्यवस्था सुधारने के लिए हुआ या व्यवस्था बनाने के लिए?



सुरेश कुमार मिश्रा प्रेमनगर एसडीओ

कागज बनाम हकीकत

अगर कागज देखें तो विधिवत तबादला आदेश, नया पदस्थापन, अवकाश का उल्लेख, प्रभारी की नियुक्ति, सब कुछ बिल्कुल सही, लेकिन अगर घटनाक्रम देखें तो नया अधिकारी अनुपस्थित, पुराने को हटाने की जल्दबाजी, बीच में नया आदेश और अंत में प्रभारी व्यवस्था, यानी कागज कह रहा है प्रशासन, और जमीन कह रही है प्रबंधन।

व्यंग्य की नजर से...

सरकारी तंत्र में अक्सर कहा जाता है की यहाँ सब कुछ नियमों से होता है, लेकिन इस मामले को देखकर लगता है की यहाँ नियमों से नहीं, नियमों के जरिए सब कुछ होता है, तबादला आदेश निकला, अधिकारी नहीं आया, पुराना चला गया, और तीसरा बैठ गया इतनी सटीक योजना तो शतरंज के खिलाड़ी भी नहीं बना पाते!

पीडब्ल्यूडी सूरजपुर में 'तिगड़ी राज':

सड़क से ज्यादा 'सिस्टम' मजबूत, सप्लाई से तय हो रही गुणवत्ता!- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सूरजपुर इन दिनों विकास कार्यों से कम और अंदरूनी समीकरणों से ज्यादा चर्चा में है, विभाग के भीतर एक कथित 'तिगड़ी' का प्रभाव इतना मजबूत बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण जैसे तकनीकी कार्य भी अब 'इंजीनियरिंग' से कम और 'सिस्टम सेटिंग' से ज्यादा संचालित होते नजर आ रहे हैं।



पीडब्ल्यूडी कार्यालय



ललित कुमार भुई कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी सूरजपुर



कल्याण सिंह पोते उप अभियंता

तिगड़ी का प्रभाव: आदेश नहीं, सैकट चलते हैं...

सूत्रों के अनुसार, कार्यपालन अभियंता के करीबी माने जाने वाले दो अधिकारी प्रेमनगर के एसडीओ सुरेश कुमार मिश्रा और उप अभियंता कल्याण सिंह पोते विभाग में असामान्य प्रभाव रखते हैं, बताया जा रहा है कि विभागीय निर्णयों में इन दोनों की भूमिका इतनी मजबूत है कि कई बार औपचारिक प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है, जबकि वास्तविक फैसले 'अनौपचारिक सैकटों' पर लिए जाते हैं, यानी आदेश फाइल में होता है, लेकिन दिशा 'तिगड़ी' तय करती है।

सड़क निर्माण में 'सप्लाई सिडिकेट' का आरोप

सबसे गंभीर आरोप प्रेमनगर क्षेत्र के सड़क निर्माण कार्यों को लेकर सामने आए हैं, सूत्रों का दावा है कि यहाँ सड़क बनने से पहले यह तय हो जाता है कि किस क्रेशर से गिट्टी या मटेरियल आएगा, किसका मिक्सर और जेएस्वी उपयोग होगा, किस सप्लायर का बिल पास होगा, किस रिजेक्ट करना है, यानी सड़क निर्माण का पहला सवाल अब 'डिजाइन क्या है?' नहीं, बल्कि 'सप्लायर कौन है?' बन गया है।

ठेकेदारों की मजबूती: काम से पहले 'सिस्टम' समझो

सूत्र बताते हैं कि ठेकेदारों के सामने दो ही विकल्प होते हैं सिस्टम के अनुसार चलो या फिर फाइल अटकने के लिए तैयार रहो, आरोप है कि यदि ठेकेदार 'पसंदीदा' क्रेशर या सप्लायर से सामग्री नहीं लेते, तो उनके बिल पास होने में देरी, तकनीकी आपत्तियाँ या निरीक्षण में खामियाँ निकाल दी जाती हैं, और यदि वही ठेकेदार 'निर्देशित सप्लायर' से सामग्री लेते हैं, तो घंटियाँ गुणवत्ता भी आसानी से पास हो जाती है।

गुणवत्ता बनाम 'कनेक्शन'

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सड़क की गुणवत्ता को लेकर उठ रहा है, तकनीकी मानकों के अनुसार, मटेरियल की गुणवत्ता, सही मिश्रण और निर्माण प्रक्रिया, इन सब पर सड़क की मजबूती निर्भर करती है, लेकिन यदि सामग्री का चयन तकनीकी आधार पर न होकर 'कनेक्शन' के आधार पर हो, तो परिणाम क्या होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है, सूत्रों का दावा अच्छी सामग्री भी रिजेक्ट हो सकती है, और खराब सामग्री भी पास हो सकती है, इस लिए एसडीओ मिश्रा आदेश माना मजबूत?

व्यंग्य में हकीकत: सड़क कम, सिस्टम ज्यादा पक्का- सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक टेंडर प्रक्रिया भी पूरी निरीक्षण

रिपोर्ट में भी संतोषजनक और भुगतान नियमित लेकिन जमीनी स्तर पर सवाल यह है कि क्या सड़कें टिकाऊ बन रही हैं? या सिर्फ कागजों में मजबूत दिखाई जा रही हैं? कहलवत बदलती नजर आ रही है जहाँ सड़क बननी चाहिए, वहाँ नेटवर्क बन रहा है।

ईई की भूमिका पर सवाल

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे सिस्टम में कार्यपालन अभियंता की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, कहा जा रहा है कि उनके करीबी अधिकारियों को खुली छूट है, और विभागीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया है, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई आरोप सिद्ध नहीं है, लेकिन लगातार उठ रहे सवाल विभाग की छवि पर असर डाल रहे हैं।

क्या कहते हैं ठेकेदार (अनौपचारिक चर्चा)

कुछ ठेकेदारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि काम करना है तो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं तो फाइल महीनों अटकती रहती है, गुणवत्ता से ज्यादा जरूरी है कि आप किससे सामग्री ले रहे हैं, ये बयान भले ही आधिकारिक न हों, लेकिन स्थिति की गंभीरता जरूर दर्शाते हैं।

जनता का सवाल: जवाब कौन देगा?

- क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी?
- क्या यह देखा जाएगा कि अवकाश और प्रभारी नियुक्ति के पीछे क्या परिस्थितियाँ थीं?
- या फिर यह मामला भी 'फाइलों में सही' मानकर बंद कर दिया जाएगा?
- जांच की जरूरत या 'रूटीन मामला'?
- क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी?
- क्या सामग्री सप्लाई और गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी?
- या फिर यह मामला भी 'रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया' मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा?

विकास या व्यवस्था?

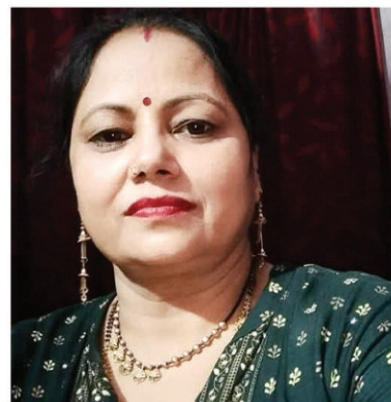
सूरजपुर पीडब्ल्यूडी का यह मामला सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, यह उस व्यवस्था का आईना है जहाँ, काम से ज्यादा नियंत्रण, और गुणवत्ता से ज्यादा 'संपर्क' मायने रखता है, अगर यही हाल रहा, तो आने वाले समय में सड़कें तो बनती रहेंगी, लेकिन उन पर चलने वाला भारोसा धीरे-धीरे टूटता जाएगा, आखिर सवाल यही है सड़क मजबूत बनेगी या सिस्टम?

सिस्टम या सेटिंग?

सूरजपुर पीडब्ल्यूडी का यह मामला सिर्फ एक तबादले की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की झलक है जहाँ कागज पर नियम चलते हैं, और जमीन पर 'सेटिंग', अगर यही हाल रहा, तो आने वाले समय में तबादले आदेश नहीं होंगे, बल्कि 'पदस्थापना की रिफ्रैक्ट' लिखी जाएगी।

एमसीबी के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सलूजा को प्रदेश कार्यसमिति में स्थान

भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की नई घोषणा कोरिया जिले को मिला मजबूत नेतृत्व



-संवाददाता-

बैकंठपुर, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार और सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की नई नियुक्तियों की घोषणा की है, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की सहमति से जारी इस सूची में कोरिया जिले को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

सुखदेव राजवाड़े बने जिला संयोजक- जारी सूची के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष सुखदेव राजवाड़े को कोरिया जिले का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक नियुक्त किया गया है, संगठन में उनके लंबे अनुभव, सामाजिक कार्यों में सक्रियता और समर्पण को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति को जिले के लिए एक मजबूत नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है।

माधुरी गुप्ता को मिली सह-संयोजक की जिम्मेदारी- बैकंठपुर की सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती माधुरी गुप्ता को जिला सह-संयोजक बनाया गया है, महिलाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह नियुक्ति संगठन को नई ऊर्जा देने वाली मानी जा रही है।



-संवाददाता-

प्रदेश स्तर पर भी मिला प्रतिनिधित्व- कोरिया जिले को प्रदेश स्तर पर भी अहम जिम्मेदारी मिली है, वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी देवधारी यादव को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है, मजदूर वर्ग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच उनके लंबे समय से किए जा रहे कार्यों को संगठन ने सम्मान दिया है।

जिले में उत्साह का माहौल- इन नियुक्तियों के बाद कोरिया जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और हर्ष का वातावरण है। संगठन के सकारात्मक कदम माने रहे हैं।

जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने नवनि्युक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा की सुखदेव राजवाड़े जी के नेतृत्व में जिले में सांस्कृतिक, सामाजिक, युवा एवं खेल गतिविधियों को नई गति मिलेगी, माधुरी गुप्ता महिला वर्ग के बीच संगठन को और मजबूत करेंगी।

संगठन का लक्ष्य- भाजपा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है, उम्मीद जताई जा रही है कि नवनि्युक्त पदाधिकारियों अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कोरिया जिले में संगठन को और सशक्त बनाएंगे।

-संवाददाता- एमसीबी/चिरमिरी, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एमसीबी जिले के वरिष्ठ नेता प्रदीप सलूजा को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया है। इस नियुक्ति से जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है।

जिले से इकलौते नेता जिन्हें मिला अवसर- प्रदीप सलूजा एमसीबी जिले के ऐसे इकलौते



भाजपा नेता हैं जिन्हें प्रदेश कार्यसमिति में स्थान मिला है। हालांकि मनेंद्रगढ़ विधायक को भी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है, लेकिन विधायक के अतिरिक्त किसी अन्य नेता में प्रदीप सलूजा ही एकमात्र हैं जो अब प्रदेश स्तर की बैठकों में भागीदारी करेंगे।

आबकारी उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई : 3 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

-संवाददाता- कोरिया/बैकंठपुर, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा टीम ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरिया जिले के जामपारा निवासी लक्ष्मण को लगभग 3 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।

मुखबिर् की सूचना पर त्वरित कार्रवाई-सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि टीम बैकंठपुर में मदिरा दुकानों की जांच कर रही थी, तभी मुखबिर् से सूचना मिली कि जामपारा निवासी लक्ष्मण अपने घर में भारी मात्रा में गांजा रखकर बिदारी कर रहा है।

सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर दबिश दी। शयन कक्ष से मिला गांजा- तलाशी के दौरान आरोपी के घर के शयन कक्ष से एक झोले में रखे 2.883 किलोग्राम (लगभग 3 किलो) गांजा बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी लक्ष्मण को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई- आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया, गिरफ्तारी के बाद उसे बैकंठपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया गया। टीम का रहा अहम योगदान- इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में मुख



आरक्षक अशोक सोनी, नगर सैनिक गणेश पांडे, रणविजय सिंह, महिला सैनिक

राजकुमारी सिंह एवं नीरज चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नशे के खिलाफ अभियान जारी- नशे के खिलाफ अभियान जारी- उड़नदस्ता टीम सरगुजा संभाग के सभी जिलों में नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरे संभाग को नशा मुक्त बनाने की दिशा में विभाग लगातार प्रयासरत है।

क्षेत्र में मचा हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में डर का माहौल है। आबकारी विभाग की इस सख्ती से साफ है कि अब नशे के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने वाली है।

नहर पर कब्जा, कागजों में सफाई! कोरिया में अवैध निर्माण को मिला वैधता का तमगा, तीन साल तक अतिक्रमण, एक आदेश में वैध! कोरिया का फैसला बना चर्चा का केंद्र

'जब सैया भाए कोतवाल'

कोरिया में अतिक्रमण बना वैध, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल



हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खेल खत्म नहीं—अतिक्रमण को ही बता दिया गया वैध रिपोर्टें कहती रहीं अतिक्रमण, आदेश ने कर दिया 'वलीन चिट'—कोरिया में बड़ा खेल उजागर

नहर भूमि पर रातों-रात निर्माण, प्रशासन ने आंखें मूंदी

पटवारी से लेकर जल संसाधन विभाग तक सब बोले 'अतिक्रमण', फिर कैसे बदला फैसला?

ग्राम पंचायत ने रोका काम, फिर भी छड़ी हो गई दीवार—किसके इशारे पर हुआ कब्जा?

अनापत्ति पत्र की नई व्याख्या से पलटा पूरा केस

राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक लाचारी? सवालों के घेरे में तहसीलदार का आदेश

विभागीय रिपोर्ट : हर स्तर पर अतिक्रमण की पुष्टि

जल संसाधन विभाग-नहर भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि

राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट-अतिक्रमण दर्ज

पटवारी रिपोर्ट-अतिक्रमण पंजी में उल्लेख

इतना ही नहीं, मामला न्यायालय तक पहुंचा और वर्ष 2024 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया

बड़ा सवाल: अधिकार किसका ?

क्या नहर भूमि पर अतिक्रमण का निर्णय जल संसाधन विभाग करेगा ?

क्या राजस्व विभाग अपनी ही रिपोर्ट को बदल सकता है ?

क्या न्यायालय के आदेश को इस तरह अप्रभावी किया जा सकता है ?

अगर इसका जवाब स्पष्ट नहीं है, तो यह भविष्य में और बड़े विवादों को दे सकता है जन्म...

मामले की शुरुआत : वैधानिक प्रस्ताव और स्वीकृति

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब साहू समाज के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय अरुण साहू, जो उस समय जिला अध्यक्ष थे, ने माता कर्मा चौक के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कराया, दिनांक 16 नवंबर 2022 को हल्का पटवारी द्वारा नक्शा और खसरा नंबर प्रस्तुत किया गया, प्रस्तावित भूमि थी खसरा नंबर 54/1 (रास्ता मद) यह भूमि कंचनपुर से अम्बिकापुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का हिस्सा थी, इस प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति मिली और आगे बढ़ते हुए, 12 अप्रैल 2023 को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत भांडी को निर्माण एजेंसी बनाकर कार्यदिशा जारी किया, यहां तक पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही थी।

कहनी में मोड़: अचानक बदली जमीन, नहर पर पहुंचा निर्माण

जब ग्राम पंचायत ने निर्धारित सड़क भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया, तभी कथित रूप से एक प्रभावशाली स्थानीय नेता के हस्तक्षेप से स्थिति बदल गई, निर्माण स्थल को बदलकर खसरा नंबर 101/15 (नहर भूमि) कर दिया गया, नहर की भूमि पर भूमि पूजन और ले-आउट तैयार कर दिया गया, यह बदलाव न केवल तकनीकी रूप से गलत था, बल्कि यह सीधे-सीधे शासकीय भूमि के दुरुपयोग की श्रेणी में आता था।



—रवि सिंह—
कोरिया, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)।
कोरिया जिले में सामने आया यह प्रकरण अब सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े करता है, तीन वर्षों तक जिस निर्माण को सरकारी रिकॉर्ड, विभागीय रिपोर्ट और न्यायालय के आदेश में अतिक्रमण माना गया, वही अचानक एक आदेश में वैध घोषित कर दिया गया, इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यही सवाल उठता है की क्या कानून अपनी जगह पर है, या फिर परिस्थितियों के हिसाब से उसे मोड़ा जा रहा है?

ग्राम पंचायत की आपत्ति : हम काम नहीं करेंगे...

इस पूरे घटनाक्रम के बाद ग्राम पंचायत भांडी ने जिम्मेदारी दिखाते हुए जनपद पंचायत को लिखित में स्पष्ट कर दिया, यह भूमि नहर विभाग की है, यहां विवाद की स्थिति है, ग्राम पंचायत इस स्थान पर निर्माण कार्य नहीं करेगी, इस कार्य के लिए प्राप्त राशि खर्च नहीं की गई है, पूरी राशि वापस जमा कर दी गई है, यह कदम दर्शाता है कि पंचायत स्तर पर नियमों का पालन करने की कोशिश की गई थी।

आधी रात का कब्जा : विवाद को सामाजिक रंग

इसके बावजूद मामला यहीं नहीं रुका, सुत्रों के अनुसार आधी रात को नहर भूमि पर जबरन कब्जा किया गया, दीवार निर्माण कर मूर्त स्थापित कर दी गई, इस अवैध कब्जे को सामाजिक और धार्मिक मुद्दा का रूप दे दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस क्षेत्र के 100 मीटर दायरे में लगभग 60 प्रतिशत भूमि एक ही समाज विशेष के लोगों की है, इसके बावजूद, जिस स्थान पर कब्जा किया गया, उसे लेकर आरोप है कि यह एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चुना गया।

प्रशासन की चुप्पी : आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं

हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद, प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया टाली जाती रही, जिम्मेदार अधिकारी मामले को लंबित रखते रहे, राजनीतिक दबाव की चर्चाएं लगातार सामने आती रहीं, यह स्थिति यह दर्शाती है कि जब सत्ता का दबाव बढ़ता है, तो प्रशासनिक इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाती है।

नहर पर बना चौक या फाइलों का खेल ?

2023 में अतिक्रमण, 2026 में नो ऑब्जेक्शन

एक ही अडवायर, दो आदेश!

एक ही न्यायालय, दो आदेश...

पहले कब्जा हटाने का आदेश, बाद में अतिक्रमण ही नहीं...

पूर्व में प्रकाशित समाचार

भांडी का 'कर्मा चौक' या फाइलों का चक्क्यू ?

राजनीतिक संरक्षण में फंसा न्याय

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तीन साल से नहीं हट पाया नहर का अतिक्रमण

अवमानना और जल्दबाजी में फैसला

जब मामला अवमानना तक पहुंचा, तब प्रशासन सक्रिय हुआ, तहसीलदार बैकुंठपुर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर समय मांगा, बाद में 6 फरवरी को दूसरे अधिकारी से सुनवाई शुरू करवाई गई, जल्दबाजी में टीम बनाकर जांच रिपोर्ट मंगाई गई लेकिन जो निष्कर्ष सामने आया, उसने पूरे मामले को और विवादित बना दिया।

सबसे बड़ा टि्वस्ट : यह अतिक्रमण है ही नहीं

तहसीलदार बैकुंठपुर द्वारा दिए गए अंतिम आदेश में कहा गया, यह अतिक्रमण का मामला नहीं है, इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पटवारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया, राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट को दरकिनारा किया गया, जल संसाधन विभाग की आपत्तियों को भी महत्व नहीं दिया गया यानी, जो दस्तावेज तीन वर्षों तक अतिक्रमण साबित करते रहे, उन्हें एक झटके में अप्रासंगिक कर दिया गया।

अनापत्ति पत्र की 'नई व्याख्या'

ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए अनापत्ति पत्र को भी नए तरीके से पढ़ा गया, मूल पत्र में स्पष्ट लिखा था, यदि संबंधित विभाग नियमानुसार निर्माण कराते हैं, तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तहसीलदार ने इसे पूर्ण अनापत्ति मानते हुए पूरे कब्जे को वैध घोषित कर दिया, यह व्याख्या ही इस मामले का सबसे बड़ा विवाद बन गई है।

प्रक्रिया में खामियां : न्यायिक सिद्धांतों की अनदेखी

इस निर्णय में कई गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां सामने आई हैं, ग्राम पंचायत (निर्माण एजेंसी) को सुनवाई में शामिल नहीं किया गया, जल संसाधन विभाग से दोबारा अभिमत नहीं लिया गया, आवेदक को भी सुनवाई में अवसर नहीं मिला, पूर्व की सभी अधिकारिक रिपोर्टों को अनदेखा किया गया, यह स्थिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना जा रहा है।

सिस्टम पर असर : खतरनाक संकेत

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह है कि शासकीय भूमि की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, राजस्व व्यवस्था की निष्पक्षता संदिग्ध हुई है, आम जनता का प्रशासन पर विश्वास कमजोर हुआ है अगर अतिक्रमण को इस तरह वैध किया जाता रहा, तो यह एक खतरनाक परंपरा बन सकती है।

न्याय या सत्ता का प्रभाव ?

कोरिया जिले का यह मामला अब एक मिसाल बन चुका है लेकिन सकारात्मक नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में, जहां नियमों के तहत शुरू हुआ कार्य, राजनीतिक हस्तक्षेप से बदला, विभागीय जांच में अवैध पाया गया, न्यायालय ने हटाने का आदेश दिया, वहीं अंत में एक प्रशासनिक आदेश ने सब कुछ उलट दिया, यह सिर्फ एक अतिक्रमण का मामला नहीं, बल्कि यह उस व्यवस्था का आईना है जहां कानून और सत्ता आमने-सामने खड़े हैं, अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर उच्च स्तर पर पुनर्विचार होता है या यह मामला भी फाइलों में दबकर इतिहास बन जाता है।

सिंघत जलाशय नहर लाइनिंग में बड़ा खेल: 8 इंच की जगह 4 इंच ढलाई का आरोप

मापदंडों की खुली अनदेखी

जानकारी के अनुसार, नहर लाइनिंग के लिए निर्धारित 8 इंच मोटाई के स्थान पर मात्र 4 इंच ढलाई की जा रही है, इसके अलावा जहां लोहे की छड़ों (रॉड) की दूरी 1 फीट होनी चाहिए, वहां लगभग 2 फीट (60 सेंटीमीटर) की दूरी पर ही रॉड लगाकर काम किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से तय मानकों का उल्लंघन है।

जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा नहर का निर्माण मानकों के अनुसार देवादा कराया जाए।

बड़े सवाल कायम

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा, ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को उम्मीद से लेकर निष्पक्ष जांच करेगा।

—राजेश शर्मा—
खड़गवा, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)।
खड़गवा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सिंघत जलाशय से जुड़ी नहर लाइनिंग निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत कर घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

तकनीकी प्रक्रिया की अनदेखी

निर्माण कार्य में कंक्रीट की मजबूती के लिए आवश्यक वाइब्रेटर मशीन का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, बिना वाइब्रेशन के ढलाई करने से कंक्रीट में खाली जगह रह जाती है, जिससे भविष्य में दरार, रिसाव और टूट-फूट की आशंका बढ़ जाती है।

मोबाइल से हो रहा निरीक्षण ?

ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं रहते और केवल मोबाइल के माध्यम से कार्य की निगरानी कर रहे हैं, जब संबंधित इंजीनियर से जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि वे दूरसे साइट पर हैं और देखकर ही कुछ बता पाएंगे। इससे निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

मिलीभगत की आशंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही बिना अधिकारियों की सलिलता के संभव नहीं है, आरोप है कि ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका और मजबूत हो जाती है।

ग्रामीणों में आक्रोश

घटिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तरह के कार्य से सरकारी धन की बर्बादी हो रही है और किसानों को मिलने वाले पानी पर भी खतरा मंडरा रहा है, यदि नहर कमजोर बनी, तो पूरी योजना प्रभावित हो सकती है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर, जिला-सुरगुजा (छ0ग0)

इशतहार
रा.प्र.क्र./34-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अमलेश प्रसाद साहू पिता राजेन्द्र शाह जाति तेली निवासी खरसिया नाका अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सुरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकारिक भूमि स्थित ग्राम अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सुरगुजा (छ0ग0) खसरा नंबर 4608/14 रकबा 0.020 हे0 भूमि को कृषि भिन्न अवासीय प्रयोजन हेतु व्यवहृतन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सही आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचारार्थ है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सूचनादि तिथि 28/3/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयवधि के पश्चात प्राप्त दवा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20/3/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

(सील)

कानून के रखवाले या कारोबार के हिस्सेदार ?



- ★ कोरिया में अवैध ईंट भट्टों और कोयला चोरी का गहरा गठजोड़
- ★ कोरिया में 'कोयला-भट्टा' सिंडिकेट का खुलासा,
- ★ कानून के रखवालों से लेकर राजनीति तक पर उठे सवाल

अवैध ईंट भट्टों के संचालन में अब पुलिसकर्मी भी हुए सलिप्त, पटना से लगे शंकर नगर के समीप पुलिसकर्मी का है अवैध ईंट भट्टा, सूत्र

अवैध ईंट भट्टे का सीधा संबंध है कोयला चोरी से, कोयला चोरी रोकने वाले ही सलिप्त हुए चोरी में : सूत्र

एक साल से बंद कोयला चोरी के कारोबार को मिल चुकी है हरि झंडी, सुशासन सरकार में कोयला चोरी वैध ?

कोयला चोरी के मामले में विपक्ष भी रहता है मौन, कोयला चोरी कारोबार को लेकर विपक्ष नहीं करता सरकार पर हमला

-रवि सिंह-
कोरिया/पटना, 22 मार्च 2026 (घटती-घटना)।
जिले के पटना नगर पंचायत से लगे शंकर नगर क्षेत्र से सामने आई एक सनसनीखेज जानकारी ने प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस

तंत्र और राजनीतिक तंत्र तीनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, सूत्रों के अनुसार, पटना थाना में पदस्थ एक आरक्षक का अवैध ईंट भट्टा संचालित हो रहा है, और यह भट्टा कथित तौर पर कोयला

चोरी के संगठित नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला सिर्फ एक अवैध कारोबार का नहीं, बल्कि कानून के रखवालों के भीतर ही पनपते अवैध तंत्र का उदाहरण बन जाएगा।

कोयला चोरी ऐसा व्यापार जहां राजनीतिक आपसी द्वेष हो जाता है समाप्त



तबादला आदेश बेअसर, अनुशासन पर सवाल

मामले में यह भी सामने आया है कि एक आरक्षक का तबादला करीब 6 महीने पहले हुआ और दूसरे का एक महीने पहले सूत्रों के अनुसार एक आरक्षक ने रवानगी ले ली, जबकि दूसरा अब तक पदस्थ बना हुआ है, इस स्थिति में पुलिस अधीक्षक के आदेशों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि आदेशों का पालन ही नहीं हो रहा, तो यह प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन के लिए गंभीर संकेत है।

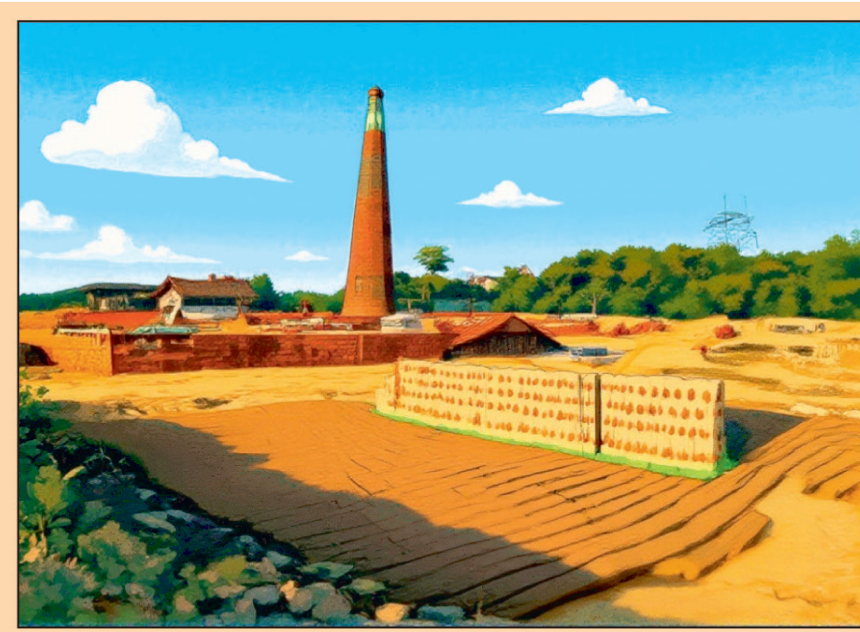


स्थानांतरण के बाद भी 'जमे' आरक्षक, उठे गंभीर सवाल

पटना थाना क्षेत्र से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, शंकर नगर के पास संचालित अवैध ईंट भट्टा एक ऐसे आरक्षक का बताया जा रहा है, जिसका स्थानांतरण पहले ही हो चुका है, इसके बावजूद वह अब तक रवानगी नहीं ले रहा और उसी थाना क्षेत्र में पदस्थ बना हुआ है, यदि सूत्रों का दावा सही है, तो यह स्थिति बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि एक ओर जहां पुलिसकर्मीयों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वहीं दूसरी ओर उसी तंत्र का हिस्सा किसी अवैध कारोबार में सलिप्त बताया जाना पूरे सिस्टम की साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

ड्रोन शराब पर, कोयला क्यों नहीं? निगरानी पर उठते सवाल

हाल ही में जिले में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कर कार्रवाई की गई, जिसे प्रशासन ने बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया, जंगलों में छिपे अवैध शराब कारोबारियों को तकनीक के जरिए पकड़ना निश्चित ही सराहनीय कदम है, लेकिन यही तकनीक कोयला चोरी जैसे बड़े और संगठित अपराध पर क्यों नहीं लागू की जा रही? सूत्रों के अनुसार, जिले में अवैध ईंट भट्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इनमें से कई का संचालन प्रभावशाली लोगों-राजनीतिक, प्रशासनिक या पुलिस से जुड़े व्यक्तियों-द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि इन गतिविधियों पर समान स्तर की निगरानी क्यों नहीं है, यदि ड्रोन तकनीक से जंगलों में शराब बनाने वालों को पकड़ा जा सकता है, तो खुलेआम सड़कों पर चल रहे कोयला परिवहन और भट्टों की निगरानी क्यों नहीं हो सकती? यह स्थिति संकेत देती है कि या तो प्रार्थमिकताएं तय करने में असमर्थ हैं, या फिर कुछ क्षेत्रों में जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, अंततः सवाल यही है कि क्या निगरानी भी अब चर्यनित हो गई है?



आरक्षक वही है जिनका स्थानांतरण हो चुका है पर यहीं पर जमे हुए हैं

पटना से लगे शंकर नगर के पास संचालित ईंट भट्टा एक आरक्षक का है जो पटना पुलिस थाने में पदस्थ है यह सूत्रों का दावा है, सूत्रों का दावा यदि सही है तो यह कानून व्यवस्था जिले की को लेकर गंभीर मामला है क्योंकि एक कानून का रखवाला अब अवैध कारोबार में खुलकर सामने है, वैसे यह वही आरक्षक है जिसका तबादला हो चुका है लेकिन वह अभी भी रवानगी लेने से बच रहा है और इसके पीछे की वजह उसका अवैध ईंट भट्टा माना जा रहा है, आरक्षक का अवैध ईंट भट्टा लगातार ईंट निर्माण कर विक्रय कर रहा है।

आरक्षक की सीडीआर निकाली जाए तो खुलेंगे राज

सूत्रों का कहना है कि यदि पटना पुलिस थाने में पदस्थ उस आरक्षक जिसके कि अवैध ईंट भट्टे संचालन की बात सामने आई है सहित अन्य आरक्षकों की सीडीआर निकाली जाए, बड़े राज जो कोयला चोरी के कारोबार से जुड़ा राज है सामने लाने में कारगर साबित होगी, बताया जाता है पटना में कोयला चोरी में अधिकांश पुलिस कर्मियों के हाथ काले हैं, और इस बात की असलियत केवल सीडीआर से सामने आ सकती है।

क्या अवैध भट्टा ही रोक रहा है रवानगी ?

सूत्रों के मुताबिक, एक आरक्षक का अवैध ईंट भट्टा लगातार संचालित हो रहा है और ईंट निर्माण व बिक्री का कार्य भी जारी है, यह भी कहा जा रहा है कि आरक्षक कोयला चोरी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, चोरी का कोयला उसके भट्टे तक पहुंचता है, इसी कारण वह थाना छोड़ने से बच रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अवैध कारोबार की वजह से ही वह अपनी नई पोस्टिंग जॉइन नहीं कर रहा?

अफीम की खेती मामले में मुखर विपक्ष कोयला चोरी विषय में मौन क्यों है ?

हाल के दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर अफीम की अवैध खेती की घटनाएं सामने आई हैं, इसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलवार है, यह विपक्ष का एक सराहनीय कार्य भी माना जाएगा जो अवैध गतिविधियों पर लगाम के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं यही विपक्ष कोयला चोरी के विषय पर मौन है, और ऐसा क्यों है यह एक विचित्रता है, विपक्ष आज का हो या कल का किसी ने कोयला चोरी को लेकर मुखरता विरोध स्थिति में दर्ज नहीं कराई जो इस सवाल को जन्म देती है कि क्या कोयला चोरी एक अवैध, और राष्ट्र राज्य द्रोह की श्रेणी का अपराध नहीं है।

एक आरक्षक का 6 महीने पहले तबादला, दूसरे आरक्षक का एक महीना पहले तबादला पर एसपी का आदेश सिर्फ आदेश की रह गया, पालन नहीं हुआ...

एक आरक्षक का तबादला 6 महीने पहले हुआ है वहीं एक का एक महीने पहले, एक ने रवानगी ली है ऐसा सूत्रों का कहना है, दूसरे ने नहीं ली है, इस तरह देखा जाए तो पुलिस अधीक्षक का आदेश आदेश ही तक सीमित है, इन आदेशों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है आरक्षक पर।



शंकर नगर का मामला: जब पुलिसकर्मी ही बन जाए 'व्यवसायी'

कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना से लगे शंकर नगर क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आ रहा है, सूत्रों के अनुसार, पटना थाना में पदस्थ एक आरक्षक का अवैध ईंट भट्टा इसी क्षेत्र में संचालित हो रहा है। खास बात यह है कि एक आरक्षक का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन वह अब तक रवानगी नहीं ले रहा, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है उसका यही कथित अवैध कारोबार, सूत्रों का दावा है कि इस ईंट भट्टे का सीधा संबंध कोयला चोरी से है, जहां चोरी का कोयला भट्टों में खपाया जाता है। यदि यह सच है, तो यह स्थिति अत्यंत गंभीर है, क्योंकि जिस पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी है, वहीं यदि इन गतिविधियों में शामिल पाई जाए, तो यह पूरे सिस्टम की साख पर गहरा धक्का है, बताया जा रहा है कि एक वर्ष तक सीमित स्तर पर चल रहा कोयला चोरी का कारोबार अब फिर से पूरी सक्रियता के साथ शुरू हो गया है। रात के समय कोयला से भरी गाड़ियां तेज रफ्तार से परिवहन करती नजर आ रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस अवैध गतिविधि को कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है?

राजनीति और कोयला : जहां विरोध भी धम जाता है...

कोरिया जिले में कोयला चोरी का कारोबार कोई नया नहीं है, लेकिन इसकी सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के नाम समय-समय पर सामने आते रहे हैं, यह भी कहा जाता है कि इस अवैध व्यापार में शामिल लोग अलग-अलग दलों से जुड़े होने के बावजूद एक साझा समझ के तहत काम करते हैं, यही कारण है कि यह मुद्दा कभी भी राजनीतिक बहस का केंद्र नहीं बन पाता। जहां एक ओर विपक्ष अन्य अवैध गतिविधियों जैसे अफीम की खेती पर खुलकर सरकार को घेरता है, वहीं कोयला चोरी जैसे बड़े और संगठित अपराध पर उसकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, अब सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आ रहा है कि इस कारोबार में कानून के रखवालों की भी कथित भागीदारी बढ़ रही है, यदि ऐसा है, तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि यह दर्शाता है कि अवैध लाभ के इस नेटवर्क में प्रभावशाली वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह ऐसा व्यापार बन चुका है, जहां राजनीति और प्रशासन दोनों की सीमाएं धुंधली हो गई हैं?

सीडीआर जांच से खुल सकते हैं बड़े राज

सूत्रों का मानना है कि यदि संबंधित आरक्षक और अन्य पुलिसकर्मीयों की सीडीआर जांच की जाए, तो कोयला चोरी के नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं, किन लोगों से संपर्क था, किन समयों में गतिविधियां हुईं, किन-किन की भूमिका रही, ऐसी जांच पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने ला सकती है।

ईंट वेक्टर ही थाने से रवानगी की तैयारी ? आरक्षक पर उठे सवाल

सूत्रों के अनुसार, तबादला होने के बावजूद एक आरक्षक पुलिस थाना पटना से रवानगी लेने में देरी कर रहा है, आरोप है कि वह लगातार निर्माणाधीन भवनों के मालिकों, ठेकेदारों और सरपंचों से संपर्क कर ईंट बेचने की कोशिश में जुटा हुआ है, चर्चा है कि आरक्षक ईंट फिरोक में है कि पर्याप्त ईंटों की बिक्री कर लेने के बाद ही वह थाने से औपचारिक रूप से रवानगी लेगा। इस पूरे मामले ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कोयला चोरी पर विपक्ष की चुप्पी क्यों ?

हाल के दिनों में प्रदेश में अवैध अफीम की खेती जैसे मामलों को लेकर विपक्ष काफी मुखर रहा है और सरकार पर लगातार हमला कर रहा है, लेकिन इसके उलट कोयला चोरी जैसे गंभीर और संगठित अपराध पर विपक्ष की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है, यह स्थिति सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह मुद्दा राजनीतिक रूप से 'संवेदनशील' है? या फिर इसमें सभी पक्षों की कहीं न कहीं हिस्सेदारी है? सबसे बड़ा सवाल यही है क्या कोयला चोरी को उतनी गंभीरता से नहीं देखा जा रहा, जितनी अन्य अवैध गतिविधियों को?

सवाल कई, जवाब अभी बाकी

यह पूरा मामला सिर्फ एक आरक्षक या एक अवैध भट्टे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर सिस्टम की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़ा करता है, क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या अवैध कारोबार के सामने प्रशासनिक आदेश कमजोर पड़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि कानून व्यवस्था मजबूत है या सिर्फ दिखावे तक सीमित।

क्या इसी कारोबार के लिए वह पटना थाना छोड़ने को तैयार नहीं

आरक्षक आज भी पटना थाने में पदस्थ है, वह तबादला होने उपरांत भी रवानगी लेने से बच रहा है, आरक्षक का अवैध ईंट भट्टे का कारोबार है, वह कोयला चोरी में सलिप्त है, चोरी का कोयला उसके अवैध ईंट भट्टे तक पहुंच रहा है ऐसा बतलाया जा रहा है, अब सवाल यह है कि क्या इसलिफ वह पटना थाना नहीं छोड़ना चाहता।

जब नेता उतरे मैदान में: एक साल थमा कोयला खेल, अब फिर क्यों सक्रिय ?

गत वर्ष कोरिया जिले में कोयला चोरी के कारोबार पर अचानक ब्रेक तब लगा, जब भाजपा जिलाध्यक्ष ने खुद मोर्चा संभाल लिया था, उन्होंने न सिर्फ छपेमारी की, बल्कि एक टीम बनाकर लगातार निगरानी भी की, इस सक्रिय हस्तक्षेप का असर यह हुआ कि वर्षों से जड़ें जमा चुके इस अवैध कारोबार की रफ्तार थम गई और करीब एक साल तक यह गतिविधि सीमित स्तर पर सिमट गई, उस दौरान कोयला चोरी

से जुड़े लोगों के बीच मायूसी का माहौल देखने को मिला था, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बड़ा और असहज सवाल भी खड़ा किया-जिस अवैध कारोबार को दशकों तक पुलिस और प्रशासन मिलकर भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके, उसे एक राजनीतिक पदाधिकारी ने अपने स्तर पर कैसे रोक दिया? क्या यह कानून व्यवस्था की विफलता नहीं दर्शाता? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी राजनीतिक

दल के जिलाध्यक्ष का काम कानून लागू कराना है, या यह जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है? यदि कानून के रखवालों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा अवैध कारोबार फलता-फूलता रहा और उसे रोकने के लिए गैर-प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी, तो यह पूरे सिस्टम पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है, चिंता की बात यह भी है कि इस वर्ष वही सख्ती नजर नहीं आ रही। भाजपा जिलाध्यक्ष

का मौन और सक्रियता का अभाव अब चर्चा का विषय बन गया है, सूत्रों के अनुसार, इसी कारण कोयला चोरी का कारोबार फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है और एक बार फिर रात के अंधेरे में यह अवैध व्यापार धड़ल्ले से चलने लगा है, आखिर सवाल यही है-क्या कानून व्यवस्था व्यक्तियों पर निर्भर है, या फिर सिस्टम खुद सक्षम है?

छत्तीसगढ़-खल्लारी मंदिर में रोपवे टूटा... 2 ट्रॉली खाई में गिरी, 1 की मौत

16 घायल, नवरात्रि पर दर्शन के लिए पहुंचे थे...



महासमुंद, 22 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक युवती की मौत हो गई। घायलों में 4 को हालत गंभीर है। यह सभी लोग चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालु रोपवे की ट्रॉली से नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक केबल टूट गया। ट्रॉली पहाड़ी से टकराई और उसमें बैठे लोग करीब 20 फीट नीचे गिर गए। इसी दौरान ऊपर जा रही ट्रॉली भी संतुलन खोकर गिर गई। उसमें बैठे लोग भी घायल हो गए। ज़्यादातर घायल रायपुर के रहने वाले हैं। कलक्टर ने कहा है कि केबल कैसे टूटा, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है।

लागभग 20 फीट नीचे पहाड़ी की चट्टान से जा टकराई। इस जोरदार झटके के कारण ट्रॉली में बैठे लोगों को गंभीर चोट आई। एक युवती ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान नीचे से ऊपर जा रही ट्रॉली भी बीच में अनियंत्रित हुई। जिससे ये ट्रॉली भी नीचे गिर गई। इसमें बैठे लोगों को भी चोट आई है। हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को निजी वाहनों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया।

नवरात्रि के कारण श्रद्धालुओं की भीड़

चैत्र नवरात्रि के कारण खल्लारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। स्थानीय लोगों ने रोप-वे के नियमित रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि समय-समय पर इसका मटेनेंस किया जाता तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं

खल्लारी रोप वे हादसे को मुख्यमंत्री साय ने बताया 'दुखद', कहा... जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिला स्थित प्रसिद्ध खल्लारी मंदिर में रोप-वे हादसे को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा और बलोदाबाजार जिले के दौर पर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कवर्धा में लोधी समाज द्वारा अर्वाचित बाई की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होंगे।



और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। महासमुंद से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर खल्लारी गांव की पहाड़ी के शीर्ष पर खल्लारी माता का मंदिर स्थित है। हर साल वार और चैत्र नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ इस दुर्गम पहाड़ी में दर्शन के लिए आती है। हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा के अवसर पर मेले लगता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युग में पांडव अपनी यात्रा के दौरान इस पहाड़ी की चोटी पर आए थे।

रायपुर में ईओडब्ल्यू अफसर बनकर टगे 9.50 लाख

केस रफा-दफा करने के नाम पर रिटायर्ड इंजीनियर से मांगे थे 10 लाख, परिचित ही निकला मास्टरमाइंड

रायपुर, 22 मार्च 2026। राजधानी रायपुर में एक रिटायर्ड इंजीनियर से लाखों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू अधिकारी बनकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने दो महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि ठगी की साजिश रचने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि पीड़ित का पुराना परिचित और भरोसेमंद साथी ही निकला। पुलिस ने पीड़ित का नाम देवलाल सिंह टैकम और आरोपी का नाम धर्मेद चौहान बताया है। यह मामला राखी थाना क्षेत्र का है। पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए देवलाल सिंह टैकम को जनवरी में कुछ अनजान नंबरों से कॉल आए। कॉल करने वालों ने खुद को एसीबी/ईओडब्ल्यू का अधिकारी बताकर उन्हें डराया कि उनके खिलाफ गंभीर शिकायत हुई है। इससे देवलाल घबरा गए। उन्होंने ये बात अपने पुराने परिचित धर्मेद चौहान को बताई, लेकिन मदद करने के बजाय धर्मेद ने इसी बात का फायदा उठाकर ठगी की साजिश रची।



धर्मेदर देवलाल को इतना डराया कि वह समझौता करने को तैयार हो गया। आरोपी ने खुद को अधिकारी बताते हुए कहा कि 'धर्मेद चौहान के माध्यम से ही वह मामला खत्म हो सकता है।'
9.50 लाख लेकर हुआ फरार, ऐसे खुला राज
खुद को बचाने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर ने धर्मेद चौहान को किस्तों में कुल 9,50,000 रुपए दे दिए। आरोपी धर्मेद जगदलपुर में टैट का व्यवसाय करता है। पीड़ित के खेतों की देखरेख भी करता था, इसलिए उसे देवलाल की कमजोरियों और पुराने कार्यक्षेत्रों की पूरी जानकारी थी। जब काफी समय बाद भी मामला पूरी नहीं हुआ, तब पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

हटिया एलटीटी एक्सप्रेस में 6 लाख का गांजा पकड़ाया

लावारिशा हालत में छोड़कर आरोपी फरार, रायगढ़ में रेलवे स्टेशन में गांजे से भरा बैग उतारा गया

रायगढ़, 22 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हटिया एलटीटी एक्सप्रेस में अज्ञात शख्स गांजा की तस्करी कर रहा था। जहां उसने गांजा से भरा बैग को छोड़कर ट्रेन से नीचे उतर गया। ऐसे में सूचना के बाद जीआरपी पुलिस द्वारा गांजे से भरा बैग को जब्त कर आगे की कार्रवाई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हटिया एलटीटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर गंतव्य के लिए रवाना हुई। जहां शनिवार को शाम को इस यात्री ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने बोगी नंबर 73 में एक लावारिशा ट्रॉली बैग देखा इस सीट पर काफी देर तक किसी भी यात्री के नहीं पहुंचने यात्रियों को इस पर किसी तरह का संदेह हुआ और इसकी जानकारी ट्रेन के टीटीई को दी गई। इसके बाद बैग से संबंधित यात्री की तलाश की गई, लेकिन इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिलने पर टीटीई ने मामले की रायगढ़ जानकारी जीआरपी और आरपीएफ को दी। जहां करीब शाम 4 बजे के आसपास जब हटिया एलटीटी एक्सप्रेस रायगढ़ के प्लेटफार्म नंबर 2 बार पहुंची, तो रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और बैग खोलकर जांच करने पर उसमें 12 पैकेटों में कुल 12 किलो 680 ग्राम गांजा मिला। जिसकी कीमत करीब 6 लाख 25 हजार है उसे जब्त करते हुए थाना ले आए और मामले में अज्ञात आरोपी के द्वारा ट्रेन के जरिये अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते पाए जाने से बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।



फैक्ट्री संचालकों को एसएसपी की सख्त चेतावनी, कहा... सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई

बिलासपुर, 22 मार्च 2026। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार हो रहे हादसों और आगजनी की घटनाओं पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी है। इससे पहले एसएसपी रजनेश सिंह ने सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी और कोनी क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों और संचालकों की आपात बैठक ली। उन्होंने बैठक में आए सभी उद्योगों के संचालकों को दो टुक कहा कि मुनाफा कमाएं, लेकिन कर्मचारियों की जान की कीमत पर नहीं। सुरक्षा मानकों को पूरा करना उनके लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य है। एसएसपी ने निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों में कोताही बरतने कवर करते हुए हार्ड-क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए। लगातार हो रही आगजनी को देखते हुए हर यूनिट में पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर और अग्निशमन यंत्र वकिंग कंडीशन में होने चाहिए। बैठक में छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार शाह, उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी समेत अन्य प्रमुख उद्योगी शामिल हुए। पुलिस विभाग की ओर से एसएसपी (सिटी) पंकज पटेल और एसएसपी (ग्रामीण) मधुलिका सिंह भी उपस्थित रहें। एसएसपी ने सभी उद्योग संचालकों से कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो समय-समय पर फैक्ट्रियों की जांच करेगी। जांच में उद्योगों के भीतर सुरक्षा मानकों से लेकर किसी भी तरह की न्यूसेंस मिलने पर उद्योग के संचालक समेत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गांजा तस्करी में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

बिलासपुर में 4.35 किलो गांजा जब्त, स्कूटी से तस्करी कर रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा

बिलासपुर, 22 मार्च 2026। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गत दिवस व्यापार विहार स्थित प्लेनेटोरियम के पीछे रेलवे लाइन के पास से स्कूटी में 4.35 किलोग्राम गांजा ले जाते हुए उसे पकड़ा। आरोपी के पास से 42,500 रुपए नकद भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार, तालापारा बजरंग चौक निवासी 29 वर्षीय कार्तिक गुप्ता को व्यापार विहार तारा मंडल के पास स्कूटी (वाहन क्र. सीजी-10 सीडी-1592) से रेलवे लाइन पार कर इंदरने नगर की ओर जाते समय रोका गया। संदेह होने पर उसकी स्कूटी की डिब्की की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध रूप से रखा 4.35 किलोग्राम गांजा और 42,500 रुपए नकद बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पृष्ठताछ के आधार पर मामले की गहन जांच



की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गांजा तस्करी में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

अविभाजित मग्न के दौरान हुए करोड़ों के आवास ऋण घोटेले में दो आरोपित 25 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर



रायपुर, 22 मार्च 2026। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और एसीबी ने 26 साल पुराने गृह निर्माण ऋण गबन प्रकरण में 'आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रायपुर' के तत्कालीन अध्यक्ष धारुण दत्त माधवानी और 'सहकारी आवास संघ मर्यादित रायपुर' के तत्कालीन आवास पर्यवेक्षक बसंत कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 18 मार्च 2026 को हुई है। गिरफ्तार आरोपितों को 25 मार्च 2026 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार जांच में पाया गया कि वर्ष 1995 से 1998 के दौरान आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रायपुर के तत्कालीन अध्यक्ष धारुणदत्त माधवानी ने अपनी समिति के 186 सदस्यों के नाम पर 1-1 लाख रुपये कुल 1 करोड़ 86 लाख रुपये का गृह निर्माण ऋण मध्य प्रदेश सहकारी आवास संघ मर्यादित, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से प्राप्त किया गया। ऋण अभिलेखों में गृह निर्माण स्थल ग्राम रायपुर एवं पंडरीकांचा दर्शाया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर उक्त प्रकरण का सत्यापन कराया गया, किन्तु सत्यापन में भी गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निर्माण कार्य पूर्ण होना बताया गया। बाद में कराये गये भौतिक सत्यापन में उक्त स्थलों पर न तो कोई मकान निर्मित पाया गया और न ही ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति वहां उपलब्ध मिले। जांच में कूटचिंत दस्तावेजों, फर्जी प्रमाण-पत्रों तथा अपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से ऋण राशि के गबन किये जाने के तथ्य सामने आये। प्रकरण के अन्य दो नामजद आरोपितों को मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में

धारा 120बी, 406, 409, 420, 467, 468, 471 भादवि तथा धारा 13 (1) (सी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज है। गिरफ्तार आरोपितों को 25 मार्च 2026 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों को पूर्व में कई बार नोटिस तामील करने का प्रयास किया गया, किन्तु वे अपने पते पर नहीं मिले तथा छिपकर रह रहे थे। ब्यूरो ने पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से पुनः परीक्षण में लेकर उनमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जिसने सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि मध्य प्रदेश सहकारी आवास संघ के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी स्व. ए.ई. ग्रैवियल द्वारा बिना समुचित जांच के ऋण आवेदन स्वीकृत कर आवास संघ मुख्यालय को अर्पित किये गये, जिसके आधार पर ऋण स्वीकृत कराया गया। उनके द्वारा ऋणों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा निर्माण के विभिन्न चरणों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किये गये। आरोपित बसंत कुमार साहू, तत्कालीन आवास पर्यवेक्षक, द्वारा भी भवन निर्मित होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया। आरोपितों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र कर कूटचिंत अभिलेखों का उपयोग करते हुए आवास संघ से गृह निर्माण हेतु धोखाधड़ीपूर्वक ऋण स्वीकृत कराया गया तथा राशि 01 करोड़ 86 लाख रुपये का बंदरबांट कर आपस में वितरित कर लिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय



रायपुर, 22 मार्च 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बलोदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम ओड्डन में बावनगढ़ आदिवासी ध्रुव गोंड समाज तुरतुरिया माता महासभा लवन के तत्वावधान में आयोजित गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर साय ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पारम्परिक गोंड रीति-रिवाज से दाम्पत्य सृज में बंधे 28 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व सुखवय दाम्पत्य जीवन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज के पदाधिकारियों की मांग पर कसडोल नगर में कंवर समाज सामुदायिक भवन व नगर पंचायत पलारी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50-50 लाख रुपए और ग्राम ओड्डन में बखड़ेद ठाना में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही ग्राम ओड्डन के शनिमंदिर से बखड़ेद ठाना तक सीसी रोड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री साय ने कहा हमारी सरकार पारम्परिक गोंड रीति-रिवाज से दाम्पत्य सृज में बंधे 28 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व सुखवय दाम्पत्य जीवन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

आप लोगों ने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष 200 करोड़ के लिए इस साल हम लोगों ने 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की दिशा में प्रधानमंत्री जन्मन योजना मील

और तेंदुपत्ता संग्रहण है। हम लोगों ने तेंदुपत्ता संग्रहण का दाम 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किया है। जंगल जाने, वनोजन का संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई-बहनों के पैरों में कांटे न चुभें, इसका भी इंतजाम हमारी सरकार ने फिर से किया है। इस साल चरण पादुका चित्रण भी किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहकों को चरण पादुका प्रदान करने के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामूहिक विवाह बहुत ही अच्छे पहल है। इस तरह के आयोजन से न केवल समाज संघटित होता है, बल्कि फिजिकल खर्च पर भी रोक लगती है। उन्होंने कहा कि अभी 10 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से 6 हजार से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में संपन्न हुआ जिसे गोल्डन बुक ऑफ वलूड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेशा जांगड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक संदीपा साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर में 2 दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई



रायपुर, 22 मार्च 2026। रायपुर नगर निगम ने मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मार्च महीने में 2 दिन शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने रामनवमी (27 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) के मौके पर यह प्रतिबंध लागू किया है। इस दौरान निगम क्षेत्र के सभी मांस दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे।
होटल-ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश : निगम आदेश

के अनुसार सिर्फ दुकानों ही नहीं, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में भी इन दिनों मांस और मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और जोन स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे।
नियम तोड़ तो जप्त होगा सामान
नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार या व्यवसायी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि दुकान का सामान भी जब्त किया जा सकता है। निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।